साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 13 27 मार्च - 02 अप्रैल 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

पाक की आर्थिक कूटनीति
पृष्ठ-6

म्यांमा में लोकतंत्र दूर की कौड़ी
पृष्ठ-7

राजनीति में अपराध की बढ़ती संलिप्तता

लोकतंत्र के लिए घातक

क्या राजनीतिक दल इस ओर ध्यान देंगे?

राजनीति और अपराध आज लगभग एक दूसरे के लिए अनिवार्य बनते जा रहे हैं, और तमाम राजनीतक दल केवल अपने हित के लिए इसमें आगे आगे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक साबित होगी।

आज पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरह रौंदा जा रहा है वह किसी से छुपा नहीं है आज जिस तरह जनतंत्र की तारीफों के पुल बांधने वाले और उसकी अच्छाईयों और ख़ूबियों को बयान करने वाले नेता गणतंत्र के नाम पर आपसी बदज़ुबानियों और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, इस से साफ ज़ाहिर है कि या तो हम प्रजातंत्र से वाक़िफ़ नहीं हैं या फिर जानबूझ कर हम उन्हें केवल अपनी तसल्ली और अहंकार के लिए बर्बाद कर रहे हैं इसकी एक बड़ी वजह भी है और वजह यह है कि आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो लोग चला रहे हैं उनके लिए राजनीति और अपराध में कोई अंतर नहीं रह गया है। आज राजनीति पूरी तरह से आपराधिक हो चुकी है। उसका अधिक अफसोसनाक पहलू यह है कि ऐसे लोगों को अपने अपराधिक होने पर कोई शर्मिन्दगी भी नहीं होती, ज़्यादा अफसोस यह है कि हमारे शासक आपराधिक होने के बावजूद किसी की ओर से उसके इज़हार पर भी आक्रोशित हुए बिना नहीं रहते। अभी हाल ही में पिछले दिनों सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सेन लोंग की टिप्पणी और उस पर हमारे नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया उसकी एक ताज़ा मिसाल है। श्री ली सेन लोंग ने सिंगापुर की संसद में भाषण देते हुए गणतंत्र के बारे में आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले नेताओं की चर्चा करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उन्होंने आज़ादी के बाद भारत में एक अच्छी व्यवस्था बनाई जो आज अंत की ओर बढ़ रही है, उन्होंने मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा कि भारत की वर्तमान लोकसभा के आधे सदस्यों के विरुद्ध दुष्कर्म और हत्या समेत कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और आगे कहा कि इन मामलात में बहुत सी घटनाएं राजनीतिक दुश्मनी की वजह से भी हो सकती हैं, मगर उनके बयान पर हमारे देश के नेताओं और शासकों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली में स्थापित सिंगापुर के राजदूत को विदेश मंत्रालय बुलाकर उस पर अपना विरोध जताया है, यह सही है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, मगर आपराधिक राजनीति का चलन एक महामारी का रूप धारण कर चुका है और विश्व के हर देश में एक दूसरे देशों की इस बारे में चर्चा होती रहती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया कूटनीतिक तौर पर ठीक कही जा सकती है मगर हमें भी तो बहरहाल यह सोचना चाहिए आख़िर हमारे नेता कहां ख़ुद को ले जा रहे हैं और कहां देश को ले जा रहे हैं क्या वाक़ई हमारी जनतांत्रिक मूल्यों का पतन नहीं हो रहा, क्या हमारी संसदीय और विधायी संस्थाओं में आपराधिक छवि वाले लोग नहीं आ गए हैं, ज़ाहिर है जब राजनैतिक दल केवल चुनाव जीतने की क्षमता वाले लोगों को ही टिकट देंगे तो आज के दौर में केवल वही हो सकते हैं जो या तो सम्पत्ति वाले हों या आपराधिक छवि के माफिया लोग, ज़रा ए.डी.आर. की रिपोर्ट पर नज़र डालिए और केवल 2014 से अब तक का विश्लेषक कीजिए यह उस पार्टी का कार्यकाल है जो अपने आप को एक अलग किस्म की पार्टी होने का दावा करती रही है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पवित्रता और स्वास्थ्य पर ख़तरा बराबर बढ़ता जा रहा है बेशक कभी आम ज़िन्दगी में बेदाग़ लोगों की वकालत की जाती थी लेकिन यह आम धारणा है कि राजनीति और अपराध एक दूसरे के समानार्थी हो चुके हैं। 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म' यानि ए.डी.आर. की रिपोर्ट भी इसकी गवाह है। अफसोस यह है कि हर सियासी दल के आपराधिक हो जाने पर चिंता जताती है और उसे रोकने का दावा करती है लेकिन चुनाव के असर पर जब टिकट वितरण का समय आता है तो दाग़ी छवि वाले प्रत्याशियों पर ही भरोसा किया जाता है। यही वजह है कि हर चुनाव के बाद ऐसे लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जिन पर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में सफल होकर आए 402 सदस्यों में से 143 (36 प्रतिशत) अपने चुनावी शपथ पत्र में अपने ऊपर आपराधिक मुकदमें की बात कही थी।

ए.डी.आर. की एक रिपोर्ट बता रही है कि वर्तमान लोकसभा में 233 सदस्य ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, रिपोर्ट में 539 सदस्यों की दस्तावेज़ात की छानबीन के आधार पर यह नतीजा निकाला है प्रत्याशियों को नामांकन करते समय यह बताना पड़ता है कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मुक़दमा तो नहीं चल रहा या लम्बित है, अगर है तो उसकी जानकारी देनी पड़ती है। ए.डी.आर. ने प्रत्याशियों के कागज़ात की जांच करके उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई है। उसका कहना है कि 2014 के मुक़ाबले में 2019 में ऐसे सदस्यों की संख्या में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपराधिक प्रवृत्ति के सदस्यों में भाजपा के 116, कांग्रेस के 29, जनता दल यू॰ के 13, डी.एम.के., 10 और तृणमूल कांग्रेस के 09 सदस्य हैं। 29 प्रतिशत सदस्यों के विरुद्ध बलात्कार, हत्या, हत्या का इरादा और महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध के केस दर्ज हैं या लंबित हैं। 2009 के मुकाबले 2019 में गंभीर आरोप वाले सदस्यों की संख्या में 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भाजपा के 5, बीएसपी के 02, कांग्रेस, एन.सी.पी., वाई.एस.आर. कांग्रेस के 1-1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार के विरुद्ध हत्या के केस हैं। जबकि 29 के विरुद्ध हैटस्पीच के आरोप के तहत केस दर्ज हैं। यह आंकड़े किसी एक पार्टी के सदस्यों के नहीं हैं बल्कि हम्माम में तो हर पार्टी नंगी नज़र आएगी। अब ज़रा वर्तमान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर एक नज़र डाली जाए। हमने केवल यू.पी. के प्रत्याशियों की तफसीर मालूम की है और वह भी केवल पांच चरणों के प्रत्याशियों की। जबकि वहां सात चरणों में चुनाव पूर्ण हुए हैं, पहले चरण में कुल 615, प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और उनमें 25 प्रतिशत यानि 156 के विरुद्ध आपराधिक मामलात दर्ज हैं। दूसरे चरण में 584 प्रत्याशियों में से 147 यानि 25 प्रतिशत के खिलाफ, तीसरे चरण में 623 में से 135 यानि 22 प्रतिशत के विरुद्ध, चौथे चरण में 621 में से 129 यानि 21 प्रतिशत के विरुद्ध और पांचवें चरण में 685 में से 185 यानि 27 प्रतिशत के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले लंबित हैं जिनमें हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। जबकि छठे और सातवें दौर में क्रमशः 27 और 28 प्रतिशत आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं जिनमें से क्रमशः 22 और 23 प्रतिशत प्रत्याशियों के विरुद्ध आपराधिक मामलात में जिनमें हत्या और बलात्कार के मुक़दमात भी शामिल हैं।

हमारे विचार में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पवित्रता और स्वास्थ्य पर ख़तरा बराबर बढ़ता जा रहा है बेशक कभी आम ज़िन्दगी में बेदाग़ लोगों की वकालत की जाती थी लेकिन यह आम धारणा है कि राजनीति और अपराध एक दूसरे के समानार्थी हो चुके हैं। 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म' यानि ए.डी.आर. की रिपोर्ट भी इसकी गवाह है। अफसोस यह है कि हर सियासी दल राजनीतिक अपराधिकरण पर चिंता जताती है और उसे रोकने का दावा करती है लेकिन चुनाव के अवसर पर जब टिकट वितरण का समय आता है तो दाग़ी छवि वाले प्रत्याशियों पर ही भरोसा किया जाता है। यही वजह है कि हर चुनाव के बाद ऐसे लोकसभा सदस्य और विध

बाक़ी पेज 11 पर

इमरान ख़ान की सरकार बचेगी या जाएगी?

अपने वक़्त के जुझारू क्रिकेटर रहे पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान ख़ान इस समय अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे मुश्किल मैच खेल रहे हैं। मैच की मुश्किलें और जटिलताएं उनके बयानों और उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ समझी जा सकती है। अब यह मैच अपने अंत के करीब आ पहुंचा है। उनकी सारी उम्मीदें अपनी गठबंधन सरकार के सहयोगियों पर जा टिकी हैं, जिनके बूते वह अपने 'एक इन स्विंग यॉर्कर' से विपक्ष के तीनों विकेट (शाहबाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फज़्लुर्रहमान) उड़ा देने का दावा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विपक्षी मोर्चे को भी मदद की उम्मीद गठबंधन के इन्हीं सहयोगियों से हैं। जिस गेंद से इमरान विकेट लेना चाहते हैं, विपक्ष उन्हीं गेंदों से वह 10 रन (वोट) लेना चाहती है, जो अविश्वास प्रस्ताव की सफलता के लिए कम पड़ रहे हैं। इसीलिए मैच के आख़िरी ओवरों में उत्तेजना हावी है और मर्यादाएं टूट चुकी है।

हाल के सालों में दक्षिण एशिया के किसी भी देश में राजनेताओं ने अपने विरोधियों के ख़िलाफ इतनी असंसदीय शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, जितना इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। यह मुठभेड़ सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी नज़र आई, जब सरकार के एक वाचाल मंत्री शेख रशीद और सहयोगी पार्टी पीएमएल क्यू के नेता चौधरी मूनिस इलाही आपस में भिड़ गए। पीएमएल के एक और नेता कामिल अली आग़ा ने भी इमरान ख़ान के एक बयान पर कड़ी टिप्पणी कर दी।

दक्षिण एशिया के लोकतांत्रिक देशों में छोटे दलों के लिए सबसे सुनहरा वक्त तब होता है, जब सरकारें मुश्किल में हों। पाकिस्तान में भी इस वक़्त ऐसी ही परिस्थितियां हैं। 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए 172 मतों की ज़रूरत है। फिलहाल तीन प्रमुख विपक्षी नेताओं द्वारा बनाए गए मोर्चे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के पास 162 सदस्यों का समर्थन है। सत्तारुढ़ गठबंधन में इमरान की पार्टी पीटीआइ की 155 सीटें हैं। इसके अलावा एमक्यूएम के 7, बलूचिस्तान अवामी पार्टी (बीएपी) के 5, ग्रेंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए के 3, मुस्लिम लीग क्यू के 5 और अवामी मुस्लिम लीग जैसी छोटी पार्टियों को मिलाकर कुल 178 सीटें हैं। विपक्ष को भी इन्हीं सहयोगियों से मदद की उम्मीद है। उसका दावा कि उसे नेशनल असेम्बली में 190 से ज़्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल है।

दरअसल, शुरू में विपक्ष को सबसे ज़्यादा उम्मीदें इमरान ख़ान की अपनी पार्टी के असंतुष्ट समूह थी, जिसकी अगुआई 2 वर्ष पहले तक इमरान के सबसे निकट रहे जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम ख़ान कर रहे हैं। कुछ अरसा पहले ख़ान ने दावा किया था कि वह 40 सांसदों के संपर्क में हैं। तब इस दावे ने सरकार के मैनेजरों में हड़कंप मचा दिया था। उसी के बाद मोहम्मद कुरैशी जैसे मंत्रियों के यह बयान सामने आए कि जनता ऐसे धोखेबाज़ों का घर घेर लेगी। उन्हें वोटिंग के लिए जाने नहीं देगी और यह भी कि ऐसे सांसदों के वोट गिने ही नहीं जाएंगे। बीते 10 मार्च को जिस तरह नेशनल असेम्बली के लांज में जमीयत के वॉलंटियर और कुछ सांसदों के ख़िलाफ़ सुरक्षा बलों की कार्यवाही हुई, उसने सरकार की इस सोच को ज़ाहिर भी किया था।

इसी के चलते अब विपक्षी दलों को गठबंधन में शामिल छोटे दलों से उम्मीद है। 05 सांसदों वाली पीएमएल क्यू ख़ुद भी इस स्थिति का लाभ उठाने की जुगत में हैं। वह राजनीतिक दृष्टि से पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज़ इमरान के नज़दीकी उस्मान बुजदार को हटाकर चौधरी परवेज़ इलाही को लाना चाहती है। माना जाता है कि इस सवाल पर वह सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत कर रही है। इसी तरह मौक़े का फायदा मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) भी उठाना चाहती है, जिसकी निगाह सिंह प्रांत के गवर्नर पद पर है।

इस बार अनिश्चय और संशय की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि सेना ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सभी को पता है कि अरसे से पाकिस्तान की राजनीति में सरकार के चेहरे को तय करने में सेना

बाक़ी पेज 11 पर

रेड लाइट आन, गाड़ी आफ अभियान का ऑडिट कराने की तैयारी में दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार प्रदूषण के ख़िलाफ़ अपने महत्वकांक्षी 'रेड लाइड ऑन, गाड़ी ऑफ (यातायात सिग्नल की लाल बत्ती जलते ही वाहन बंद कर दो) अभियान का तीसरे पक्ष से ऑडिट करवाने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी सांझा की।

राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 16 अक्तूबर 2020 को शुरू किए गए इस अभियान के तहत चालकों को यातायात लाइट के हरे होने तक अपनी गाड़ी का इंजन बंद रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक अधिकारी ने कहा, 'अभियान का तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने का प्रस्ताव पर्यावरण मंत्री के कार्यालय को भेजा गया है। हम अनुमति मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम में इस अभियान के प्रभाव का आंकलन करने का प्रयास करेंगे।' एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह अभियान इस वर्ष भी लागू करने की तैयारी है।

उन्होंने कहा, 'किसी भी अभियान की सफलता जनता की भागीदारी पर निर्भर करती है। प्रदूषण के ख़िलाफ़ लड़ाई में लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।' अक्तूबर 2020 में आइटीओ यातायात सिग्नल पर अभियान की शुरूआत के अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि राजधानी में यदि चालक यातायात सिग्नल पर प्रतीक्षा करते समय अपने वाहन के इंजन को बंद कर देते हैं तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 15 से 20 फीसद तक कमी लाई जा सकती है।

पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) के आंकड़े दर्शाते हैं कि अगर लोग यातायात सिग्नल पर अपने वाहन के इंजन बंद कर दें तो प्रदूषण में 13 से 20 फीसद तक की गिरावट आ सकती है। सरकारी अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में पीएम-2.5 सूक्ष्म कणों के 28 फीसद उत्सर्जन के लिए परिवहन क्षेत्र ज़िम्मेदार है। इसके अनुसार दिल्ली की आबोहवा में मौजूद 80 फीसद नाइट्रोजन ऑक्साइड और कॉर्बन मोनोऑक्साइड के पीछे वाहनों से होने वाले प्रदूषण का हाथ है।

दिल्ली में इस समय कुल 1.33 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं। राजधानी दिल्ली में वाहनों की संख्या 2005-06 में प्रति एक हज़ार आबादी पर 317 से बढ़कर 2019-20 में 643 पर पहुंच गई थी। सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत दाख़िल एक आवेदन पर मिले जवाब के अनुसार, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021-22 में इस अभियान के प्रचार पर 10.46 करोड़ रुपए ख़र्च किए थे।

'रेड लाइट ऑन गाड़ी आफ' अभियान के तहत पर्यावरण विभाग शहर के प्रमुख चौराहों पर स्वयंसेवी तैनात करता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यातायात सिग्नल पर रुकने के दौरान लोग गाड़ी का इंजन बंद कर दें। स्वयंसेवा चालकों को वाहनों से होने वाले प्रदूषण के ख़िलाफ़ जागरुक करने वाली पर्चियां भी बांटते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पर्यावरण विभाग ने अभियान के आख़िरी चरण में बीते वर्ष 18 से 18 दिसंबर के बीच दो पोलियों (सुबह आठ से दपहर दो बजे और दोपहर दो से रात आठ बजे) में लगभग 700 स्वयंसेवियों को तैनात किया था। अधिकारी के मुताबिक, सरकार हर स्वयंसेवी को रोज़ाना 700 रुपए का भुगतान करती है।

जल भराव की समस्या - मिलेगी जल्द राहत

बारिश के दिनों में होने वाली जलभराव की समस्या दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने कार्य योजना बनाकर काम शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि नालों की सफाई से लेकर अन्य ज़रूरी काम मानसून से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। इसके लिए नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। यह ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बारिश शुरू होते ही राजधानी में जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है। पिछले कुछ सालों से यह समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। मिन्टो ब्रिज, पुल प्रह्लादपुर सहित राजधानी के कई स्थानों पर जलजमाव की वजह से आवागमन बंद हो जाता है। इससे सड़कों पर दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। पिछले वर्ष बारिश के मौसम में कनाट प्लेट, चाणक्य पूरी, व इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित कई प्रमुख सड़कों पर पानी जमा होने से स्थिति विकट हो गई थी। वहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पानी भरने से कई घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बंद रही थी। राजधानी की यह स्थिति किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए ठोस क़दम उठाने की ज़रूरत है। इस दिशा में दिल्ली सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

समस्या का मुख्य कारण राजधानी के नालों की समय पर सफाई न होना है। इससे नालों का पानी सड़कों पर पैल जाता है। कई बार नालों से निकलने वाली गाद वहीं छोड़ दी जाती है, जिससे बारिश होने पर वह फिर से नालों में चली जाती है। उम्मीद है कि इस बार यह स्थिति नहीं होगी। समय रहते छोटे बड़े सभी नालों को साफ कर वहां से गाद हटाने की व्यवस्था कर ली जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने 147 स्थानों की पहचान कर वहां जलजमाव को रोकने के लिए काम शुरू कर दिया है, जिसे मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि सरकार के इस क़दम से दिल्लीवासियों को बारिश में राहत मिलेगी।

संपादकीय

शांति मिशन

महंगाई से गहराते संकट

जैसाकि अनुमान था 05 राज्यों के चुनाव पूरे होते ही सरकार पेट्रोल-डीजल और सिलेंडर पर रेट बढ़ाएगी, वैसा ही हुआ। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ाई ही हैं साथ सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए हैं। आम जनता महंगाई से पहले से ही त्रस्त थी और अब ये बढ़ी हुई कीमतें जनता के लिए किसी कुल्हाड़ी की चोट से कम नहीं है, इससे अब सब चीज़ों पर पैसे बढ़ने तय हैं। महामारी की रफ्तार भले मंद पड़ गई हो, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। भू-राजनीतिक परिस्थितियां इसमें खाद का काम कर रही हैं। कमाई के अभाव में महंगाई की ऊर्ध्व दिशा आम आदमी को किस दशा में पहुंचाएगी, कह पाना मुश्किल है। अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में महंगाई और कमाई को केन्द्र में नहीं रखा गया तो देश की दशा भी दयनीय होगी। महंगाई दर के ताज़ा आंकड़े फिलहाल कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। महंगाई दर इस वक्त आठ माह के उच्च स्तर पर हैं लगातार दूसरे माह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की लक्षित अधिकतम सीमा के पार। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) पर आधारित खुदरा महंगाई दर फरवरी में बढ़कर छह दशमलव सात प्रतिशत हो गई। बीती जनवरी में यह छह दशमलव एक प्रतिशत थी। इसी तरह थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित थोक महंगाई दर बीते फरवरी में बढ़कर तेरह दशमलव एक एक प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में बारह दशमलव नौ प्रतिशत थी। चिंता की बात यह कि थोक महंगाई दर लगातार ग्यारह माह से दो अंकों में बनी हुई है। नवंबर 2021 में यह चौदह दशमलव नौ प्रतिशत के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। दिसंबर में थोड़ा नीचे आई, फिर भी तेरह दशमलव पांच छह प्रतिशत पर। फरवरी 2021 में थोक महंगाई दर चार दशमलव आठ तीन प्रतिशत थी।

थोक महंगाई दर बढ़ने दर बढ़ने से विनिर्माण लागात बढ़ती है और अंत में उसकी कीमत आम उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ती है। खुदरा महंगाई दर में मौजूदा वृद्धि इसी का परिणाम है। खुदरा महंगाई दर में वृद्धि का मूल कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि है। महामारी के कारण लंबे समय तक ठप आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने से कच्चे माल की मांग तेजी से बढ़ी है। जबकि आपूर्ति महामारी से पहले की स्थिति में नहीं पहुंच पाई है। इसके पीछे निर्यातक देशों का कुछ लालच, तो कुछ बाहरी परिस्थितियां ज़िम्मेदार हैं। अब इसमें रूस/यूक्रेन युद्ध की नई परिस्थिति जुड़ गई हैं। युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह बाधित हुई है। परिणामस्वरूप पूरी दुनिया ऊंची कीमतों की तपिश से झुलसने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत सौ डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई है। इसके और ऊपर जाने की आशंका है। भारत अपनी ज़रूरत का 80 फीसद से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता हैं। एक अनुमान के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत दस फीसद बढ़ने से शून्य दशमलव चार फीसद तक बढ़ जाती है और जीडीपी विकास दर को लगभग शून्य दशमलव बीस फीसद का नुकसान होता है। यूक्रेन संकट के बाद से कच्चे तेल की कीमत में 25 फीसद से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। अमेरिकी केन्द्रीय बैंक-फेडरल रिजर्व ने चालीस साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंची महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दर में पच्चीस आधार अंकों की वृद्धि की योजना बनाई हैं इस वृद्धि के बाद कच्चा तेल और महंगा हो जाएगा। भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा। आम आदमी के साथ ही अर्थ व्यवस्था के लिए यह मुश्किल भरी परिस्थिति होगी।

खुदरा महंगाई दर का ताज़ा आंकड़ा एक विचित्र चित्र प्रस्तुत करता है, जो विशेषकर देश की ग्रामीण आबादी के लिए चिंताजनक है। बीते फरवरी में ग्रामीण महंगाई दर छह दशमलव तीन आठ प्रतिशत और शहरी महंगाई दर पांच दशमलव सात पांच फीसद रही थी। जबकि फरवरी 2021 में तस्वीर बिल्कुल उलट थी - ग्रामीण महंगाई दर चार दशमलव एक नौ प्रतिशत और शहरी महंगाई दर पांच दशमलव नौ छह फीसद। शहरों की तुलना में गांवों में महंगाई दर का ऊंचा होना नए नकारात्मक आर्थिक रुझान का संकेत है, वह भी खाद्य पदार्थों की महंगाई के कारण। गांवों में खाद्य महंगाई दर पांच दशमलव आठ सात प्रतिशत रही है, तो शहरी में पांच दशमलव सात छह फीसद। महंगाई की यह दर तब है, जब मांग महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। यह महंगाई मांग के कारण नहीं है। आरबीआई ने फरवरी 2022 में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा था कि घरेलू मांग का आधार निजी उपभोग अभी भी महामारी से पूर्व के स्तर पर नहीं पहुंच पाया हैं केन्द्रीय बैंक ने अपनी नीतिगत दर यानि रेपो रेट चार प्रतिशत पर यथावत रखी थी। बाज़ार में मांग बढ़ाने के मक़सद से आरबीआइ ने पिछले बीस माह से नीतिगत दर में कोई वृद्धि नहीं की है लेकिन कर्ज़ बांटने पर केन्द्रित आरबीआइ का यह क़दम, महामारी के बीच बने अस्थिर वित्तीय वातावरण के कारण बहुत कारगर साबित नहीं हो पाया है। अलबत्ता इसका उलटा असर दिखा है। बैंकों ने जमा पर ब्याज़ दर घटाई तो बुज़ुर्गों, विधवाओं, पेंशनधारकों, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों का जीवन कठिन हो गया। ब्याज़ से होने वाली आय घटी तो बजट बिगड़ गया और ख़र्च में कटौती करनी पड़ी। इससे जहां एक ओर बाजार में मांग घटी, वहीं दूसरी ओर संबंधित लोगों की सामाजिक सुरक्षा को भी चोट पहुंची है।

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में यानि जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान खुदरा महंगाई दर पांच दशमलव सात फीसद रहेगी। लेकिन जनवरी, फरवरी के आंकड़े और मार्च के रुझान इस अनुमान को असंभव बना रहे हैं। फिर भी महंगाई पर नियंत्रण के जो उपाय आरबीआइ के पास हैं, उसे आज़माने को लेकर उसके हाथ बंधे हुए हैं। मांग बढ़ाने के जिस उद्देश्य से बैंक ने नीतिगत दर को चार फीसद के निम्न स्तर पर अब तक बनाए रखा है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। अर्थ व्यवस्था महामारी से पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाई है। महंगाई जब बाजार में मांग बढ़ती है, तब आरबीआई ब्याज दर बढ़ा कर मांग घटाने की कोशिश करता हैं कमाई न होने से यहां तो मांग पहले से घटी हुई है। कमाई का आधार, रोज़गार बाज़ार में हा-हाकार मचा हुआ है। सेंटर फर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी (सीएमआइई) के आंकड़े बता रहे हैं कि बीती फरवरी में बेरोज़गारी दर आठ दशमलव एक शून्य फीसद पर पहुंच गई, जो जनवरी में छह दशमलव पांच सात प्रतिशत थी। मार्च में भी अभी यह लगभग साढ़े सात फीसद बनी हुई है। यानि जो रोज़गार से कमाई कर सकते हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है और जो ब्याज़ की कमाई पर आश्रित हैं, उनका यह आधार खिसक गया है। लेकिन महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने से मांग के और नीचे जाने की आशंका है। इससे रोज़गार घटेंगे। अर्थव्यवस्था डांवाडोल होगी।

महंगाई पर नियंत्रण का दूसरा रास्ता आपूर्ति को बढ़ाना और करों को घटाना है लेकिन सरकारी खज़ाना पहले से ख़ाली है और कर्ज़ का बोझ जीडीपी के नब्बे प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुका है। विनिवेश के ज़रिए राजस्व जुटाने का रास्ता भी बहुत फलदायी नहीं दिख रहा है। ऐसे में सरकार के पास अधिक गुंजाइश नहीं बच रही। न कर घटा कर राहत देने की और न महंगाई के बढ़ते दबाव को पहले से दबी-कुचली जनता के ऊपर डालने की ही। एक ओर कुंआ, तो दूसरी ओर खाई। महंगाई की आर्थिक मार तो पीड़ादायक है ही, सामाजिक मार अधिक दर्दनाक हैं। आर्थिक संकट से त्रस्त लोग खुदकुशी जैसा क़दम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। समाज पतन की ओर बढ़ता है, तो मानवीय अपराध को बढ़ावा मिलता हैं कुल मिलाकर आगे की राह कठिन है और इस कठिन राह को पार पाने जिस कौशल की ज़रूरत है, उसका नाम है - बाज़ार से मुक्ति। यही है महंगाई का मुक्ति मार्ग, जिसकी वकालत महात्मा गांधी ने की थी।❑❑

हज़रत उमर रज़ि॰ का फौजी निज़ाम

फौजी बारके

फौज के रहने के लिये बारके थी कूफा, बसरा, फिसतात ये तीनों शहर तो दरअसल फौज के क़याम और बूदबाश के लिये ही आबाद किये गये थे, मौसुल में अजमियों के ज़माने का एक क़िला चन्द गिर्जे और मामूली मकानात थे, हर समा बिन अरफज़ा अजदी (गवर्नर मौसल) ने हज़रत उमर रज़ि॰ की हिदायात के अनुसार दाग बेल डालकर इसको शहरी सूरत में आबाद किया और अरब के विभिन्न कबीलों के जुदा जुदा मोहल्ले बसाये।

घोड़ों की परदाख़्त

हर जगह बड़े-बड़े अस्तबल खानें थे जिनमें चार-चार हज़ार घोड़े हर वक़्त साजो सामान के साथ तैयार रहते थे, ये सिर्फ इसलिये तैयार रखे जाते थे कि अचानक ज़रूरत पेश आ जाये तो 32 हज़ार सवारों का रिसाला तैयार हो जाये। सन 17 हिजरी में जजीरा वालों ने अचानक बग़ावत कर दी तो यही तदबीर फतेह दिलासकी, इन घोड़ों की परवरिश और तरबिअत का बहुत अहतमाम किया जाता था, मदीना मुनव्वरा का इंतज़ाम हज़रत उमर रज़ि॰ ने ख़ुद अपने अहतमाम में ले रखा था, शहर से चार मंज़िल पर एक चरागाह तैयार कराई थी, और ख़ुद अपने गुलाम को जिसका नाम हनी था इसकी हिफाज़त और निगरानी के लिये मुक़र्रर किया था, इन घोड़ों की रानों पर दाग़ के द्वारा ये अल्फाज़ लिखे जाते थे। सन 19 हिजरी में जब यजीद बिन अबू सुफियान का इंतेक़ाल हुआ तो इनके भाई को इत्तला दी कि सवाहिल शाम पर ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है।

हज़रत उमर रज़ि॰ ने इसी वक़्त हुक्म भेजा कि सारे क़िलों की नये सिरे से मरम्मत की जाये और इनमें फौजें मुरत्तब की जाये, इसके साथ तमाम दरयाई मंज़रगाहों पर पहरा वाले तैनात किये गये और आग से रोशन रखने का इंतज़ाम किया जाये।

इसकंदरिया में ये इंतज़ाम था कि उमरु बिनुल आस रज़ि॰ की अफसरी में जिस क़दर फौजें थी इसकी एक चौथाई इसकंदरिया के लिये ख़ास थी, एक चौथाई साहिल के मक़ामात पर रहती थी, बाक़ी आधी फौज ख़ुद उमर बिनुल आस के साथ फिसतात में रहती थी ये फौजें बड़े बड़े एवानों में रहती थी और हर एवान में उनके साथ एक उरेफ रहता था जो इनके कबीले का सरदार होता था और जिसकी मारफत उनको वेतन तकसीम होता था एवानों के आगे सहन के तौर पर बड़ी ज़मीन होती थी।

16 हिजरी में जब हरकुलिस ने दरिया की राह से मिस्र पर हमला करना चाहता तो हज़रत उमर ने तमाम सवाहिल पर फौजी छावनियां तैनात कर दी, यहां तक उमर बिनुल आस रज़ि॰ की मातहती में जिस क़दर फौज थी इसकी एक चौथाई इन्हीं स्थानों के लिये रिज़र्व कर दी। इराक़ में बसरा और कूफा अगरचे ख़ुद सुरक्षित स्थान थे, चुनांचे खास कूफा में चालीस हज़ार सिपाही मौजूद रहते थे और इंतज़ामये थे कि इनमें से दस हज़ार बैरूनी मुहमात में मसरूफ रखे जाये, परन्तु इन ज़िलों में अज़मियों की जो छावनियां पहले से मौजूद थी, दोबारा तामीर करके फौजी ताक़त से मज़बूत कर दी गई, खरीबा और जाकूबा में सात छोटी छोटी छावनियां थी वह सब नये सिरे से बनाई गई, सूबा खोजिस्तान में निहायत कसरत से फौजी छावनियां क़ायम की गई, चुनांचे नहरतीरी, मनाजिर, सोकुल अहवाज, सरक हरमुजान सोस, बनयान जंदी साबोर, महरजा नकदक ये सब स्थान फौजों से मामूर हो गये थे और आज़बाइजान की छावनियों में हमेशा दस हज़ार फौज मौजूद रहती थी। (जारी)

मायावती का साथ जिन वोटरों ने छोड़ा, उनमें से भाजपा से अधिक एसपी के साथ गए

चन्द्रशेखर आज़ाद

05 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद जिस एक खास बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है, वह है अनुसूचित जाति वर्ग के वोटिंग पैटर्न में बदलाव की। ख़ासतौर पर यूपी में उसके भाजपा के साथ जाने की बात हो रही है, जिसकी वजह से बीएसपी जहां एक सीट पर ठहर गई, वहीं भाजपा मुश्किल हालात में लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंचने में सफल हो गइ। अब भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई आसान कही जाने लगी है। भीम आर्मी चीफ चन्द्रशेखर आज़ाद से संबंध में उनकी राय जानने की कोशिश की गई, पेश है चन्द्रशेखर जी से इन तमाम सवालों के जवाब :-

प्रश्नः- उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कोर वोट के भाजपा में शिफ्ट होने की बात कही जा रही है। दिख भी रही है कि बीएसपी केवल एक सीट जीत पाई। क्या वजह देखते हैं?

उत्तरः- यह सोचने का विषय बहन मायावती का है जिस वर्ग ने उन्हें राजनीतिक ताक़त दी, जिसकी वजह से वह देश के सबसे बड़े राज्य की चार बार मुख्यमंत्री हुईं, उस वर्ग ने अचानक उनसे बेरुख़ी क्यों इख़्तियार कर ली? कोई न कोई वजह तो होगी ही। रही बात, उसके भाजपा में शिफ्ट होने की तो मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि बीएसपी से अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट शिफ्ट हुआ, उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को गया है।

प्रश्नः- माना तो यह भी जा रहा है कि 'लाभार्थी' के रूप में जो नया वोट बैंक तैयार हुआ, उसमें बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति का वर्ग का ही है। 'लाभार्थी' वोट बैंक भाजपा को गया। एसपी को जाता तो उसकी सरकार नहीं बन जाती?

बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के संविधान पर अगर किसी वर्ग को सबसे ज़्यादा भरोसा है तो अनुसूचित जाति वर्ग को ही है। जो भाजपा बाबा साहेब के संविधान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हो, वह उसे कैसे वोट कर सकता है। यह प्रचारित होने पर कि यूपी की लड़ाई एसपी और भाजपा के बीच है तो संविधान बचाने के लिए उसके पास भी एसपी के साथ जाने के सिवाय और विकल्प नहीं था।

उत्तरः-यह भाजपा का सुनियोजित प्रचार है कि उसे बीएसपी का वोट शिफ्ट हुआ है। 2017 के चुनाव में बीएसपी को करीब 22 प्रतिशत वोट मिला था, इस बार उसे 12 प्रतिशत ही मिला। दस प्रतिशत की शिफ्टिंग दिख रही है। भाजपा को 2017 के चुनाव में 39 प्रतिशत वोट मिला था। अगर भाजपा का वोट उसके साथ गया होता तो यह 49 प्रतिशत हो जाना चाहिए था लेकिन उसके वोट प्रतिशत में सिर्फ दो प्रतिशत की ही वृद्धि हुई, उधर समाजवादी पार्टी वोट में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं यह वोट किसका है? अपर कास्ट का वोट समाजवादी पार्टी को मिला नहीं। यह अनुसूचित वर्ग का ही वोट है।

प्रश्नः- अनुसूचित जाति वर्ग के समाजवादी पार्टी के साथ जाने की संभावना कम रहती है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के बावजूद एसपी को बीएसपी का कोर वोट नहीं मिल पाया था..?

उत्तरः- बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के संविधान पर अगर किसी वर्ग को सबसे ज़्यादा भरोसा है तो अनुसूचित जाति वर्ग को ही है। जो भाजपा बाबा साहेब के संविधान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हो, वह उसे कैसे वोट कर सकता है। यह प्रचारित होने पर कि यूपी की लड़ाई एसपी और भाजपा के बीच है तो संविधान बचाने के लिए उसके पास भी एसपी के साथ जाने के सिवाय और विकल्प नहीं था।

प्रश्नः- बीएसपी चीफ में इस बार पहले जैसा जोश दिखा ही नहीं, क्या वजह रही इसकी?

उत्तरः- उनके भीतर क्या चल रहा था, यह वह ही बता सकती हैं

प्रश्नः- अनुसूचित जाति वर्ग के एक नए हीरो के रूप में आपका उदय हुआ, लेकिन चुनाव में अनुसूचित वर्ग का भरोसा आप नहीं जीत पाए। क्या वजह देखते हैं?

उत्तरः- मैं किसी अनुसूचित जाति बहुल सीट से चुनाव लड़ने चला जाता तो आराम से विधायक हो जाता, लेकिन मैंने सामान्य सीट को चुना और वह भी मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़। किसी नेता ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने चुनाव नहीं जीता लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि अनुसूचित वर्ग के इस बेटे में बड़ी से बड़ी राजनीतिक शख़्सियत से टकराने की हिम्मत है। जहां तक पार्टी की बात है, यह हमारा पहला चुनाव था। भाजपा ने पूरा चुनाव जिस तरह से मैनेज कर रखा था, उससे पार पाना आसान नहीं था। अनुभव मिला, आगे के चुनाव में इसका असर दिखेगा।

प्रश्नः- पंजाब में अनुसूचित जाति वर्ग से सीएम बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? खुद चन्नी भी दोनों जगह से हार गए

उत्तरः- अनुसूचित वर्ग ने अरग वहां कांग्रेस का समर्थन नहीं किया होता तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति होती पंजाब में। रही बात चन्नी के हाराने की तो उनका आंतरिक कलह तो ज़िम्मेदार रही ही, साथ ही जातीय मानसिकता भी। तमाम जातियों को यह बात रास नहीं आ रही थी कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई सीएम हो।

मैंने सामान्य सीट को चुना और वह भी मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़। किसी नेता ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। मैंने चुनाव नहीं जीता लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि अनुसूचित वर्ग के इस बेटे में बड़ी से बड़ी राजनीतिक शख़्सियत से टकराने की हिम्मत है। जहां तक पार्टी की बात है, यह हमारा पहला चुनाव था। भाजपा ने पूरा चुनाव जिस तरह से मैनेज कर रखा था, उससे पार पाना आसान नहीं था।

प्रश्नः- 2024 का क्या भविष्य देखते हैं?

उत्तरः- इतना तय है कि भाजपा की धर्म की आंधी सुविधा की राजनीति से नहीं रोका जा सकता। अगर पार्टियां यह सोचती हैं कि चुनाव से तीन माह पहले सक्रिय होकर भाजपा को हरा देंगी तो यह गलत है। भाजपा को हराने के लिए 24X7 की प्रतिबद्धता चाहिए। भाजपा जो ज़हर बो रही है उसको उसी वक्त बेअसर करना होगा।

प्रश्नः- क्या कांग्रेस, अखिलेश ओर मायावती को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे.?

उत्तरः- जो प्रयास करने थे, वे सब मैंने कर लिए। अब अकेले चलने की ठान ली है। अपने काडर को मज़बूत करूंगा, उसके ज़रिए बहुजन समाज को गोलबंद करूंगा। मेरा कारवां अब रुकने वाला नहीं है।❑❑

मैं दबंगई वाले अंदाज़ में केन्द्रीकरण के ख़िलाफ हूँ

डॉ. पलानिवेल

तमिलनाड के वित्त मंत्री डॉ. पलानिवेल त्यागराजन मानते हैं कि अगर विकास ग़रीबों में भी सबसे गरीब की ज़िन्दगियों तक पहुंचने में नाकाम रहे तो जीडीपी के आंकड़ों का ख़ास मतलब नहीं रह जाता, पेश है वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के विश्लेषक रह चुके वित्त मंत्री के साथ एक साक्षात्कार के प्रमुख अंशः-

प्रश्नः- आपके मुख्यमंत्री तमिलनाडू को एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं..?

उत्तरः- एक लक्ष्य होना अच्छी बात है क्योंकि यह आपको जवाबदेह बनाता है। तीन वर्ष में एक खरब डॉलर की अर्थ व्यवस्था बनने के लिए हमें सामान्य तौर पर 14-14.5 फीसद दर हासिल करने की ज़रूरत है जिसमें महंगाई भी शामिल है। महंगाई फिलहाल 6.5 प्रतिशत के आसपास है, अगर मैं इसे निकाल दूं तो इसका मतलब है कि मुझे करीब 7.5-8 फीसद की विकास दर चाहिए, जिसे हासिल करना मुश्किल नहीं है।

प्रश्नः- तमिलनाडू ने औद्योगिक राज्य बनने की कोशिश करते हुए भी हमेशा कल्याणकारी राज्य होने में यकीन किया है। आप बही-खातों में संतुलन कैसे लाते हैं?

उत्तरः- यह धारणा ही बुनियादी तौर पर ग़लत है कि कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी या औद्योगिकतावादी राज्य नहीं हो सकता। दुनिया भर में कल्याणकारी समाज आर्थिक भेदभाव कम करने और समावेशी होने, सर्वश्रेष्ठ अर्थ व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भारत को लें, तो तमिलनाडू इन सब चीज़ों पर किसी से भी ज़्यादा ख़र्च कर सकता है और मानव तथा सामाजिक विकास संकेतकों, हाई स्कूलों/कॉलेजों में सकल नामांकन अनुपात वगैरह में उसके नतीजे प्रथम राज्यों में से एक है। आप जितने ज़्यादा कल्याणकारी और परवाह करने वाले होंगे..आपके यहां उत्पादकता और वृद्धि भी उतनी ही ज़्यादा होगी इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है।

प्रश्नः- आपके श्वेतपत्र ने संसाधनों में केन्द्र के घटते योगदान की ओर उंगली उठाई। यह रिश्ता अब गैर बराबरी के किस स्तर पर खड़ा है?

उत्तरः- सैद्धांतिक स्तर पर मैं जबरन केन्द्रीकरण की धारणा के ही ख़िलाफ़ हूं। पर अभी मान लें कि यह मौजूं नहीं हैं अमल के स्तर पर दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक क़िस्म की योजना बनाना मूर्खतापूर्ण है। स्वच्छ भारत की मिसाल लें। उन्होंने कहा कि हमने टॉयलेट बनाए, कोई परेशानी नहीं। वे कहते हैं कि हम सीधे स्थानीय निकाय के पास जाएंगे, उन्हें पैसा देंगे और वे टॉयलेट बनाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां दिखाई गई हैं कोई परेशानी नहीं। मगर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आप जब टॉयलेट बना देते हैं तो पानी सप्लाई कौन करेगा? केन्द्र तो नहीं करेगा, बराबर? पंचायत या निगम करेगा। आप हरेक पंचायत की जलापूर्ति दिल्ली से नहीं संभाल सकते, बराबर? यह फैसला स्थानीय लोगों को करना चाहिए।

यह धारणा ही बुनियादी तौर पर ग़लत है कि कल्याणकारी राज्य पूंजीवादी या औद्योगिकतावादी राज्य नहीं हो सकता। दुनिया भर में कल्याणकारी समाज आर्थिक भेदभाव कम करने और समावेशी होने, सर्वश्रेष्ठ अर्थ व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं।

प्रश्नः- तमिलनाडू को दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य माना जाता है, मगर 2011 से राष्ट्रीय स्तर पर आपकी रैंकिंग गिर रही है..?

उत्तरः- इन चीज़ों को आप कैसे आंकते हैं? फिलहाल तमिलनाडू की प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,000-15,000 रुपए है, जो गुजरात से कम है लेकिन तमिलनाडू में 15 वर्ष से छोटी एक भी लड़की ऐसी नहीं जो स्कूल में न हो। गुजरात में उनमें से 15-20 प्रतिशत स्कूल में नहीं हैं किस किस्म का विकास मैं चाहता हूं? तमिलनाडू में हर 1000 लोगों पर चार डॉक्टर है, गुजरात में हर हजार लोगों पर एक डॉक्टर है। किस किस्म का समाज मैं चाहता हूं। जीडीपी के आंकड़े ही सब कुछ नहीं हैं हमारी ज़िन्दगी जीने का तरीका है जिसकी मैं रक्षा करना और बनाए रखना चाहता हूं, जिसे मुख्यमंत्री द्रविडियन मॉल कहते हैं। हम इसे लागू करेंगे और बीते 10 वर्ष में जो भी कमियां रहीं हैं, अगले पांच साल में हम फिर शीर्ष पर लौटेंगे। मुझे 100 प्रतिशत यकीन है।

विश्सनीयता खो रहा 'चुनाव आयोग

बीते दिनों एक टेलिविजन चैनल ने उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के साथ साक्षात्कारों पर आधारित एक स्टोरी चलाई जिन्होंने दावा किया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने धन दिया और अपना वोट नहीं डालने के लिए कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न मिटने वाली स्याही जबरन उनकी उंगलियों पर लगाई गई ताकि यह पता लगे कि वे पहले ही वोट डाल चुके हैं।

लगभग सभी अन्य समाचार चैनलों तथा समाचार पत्रों ने इस स्टोरी को नज़रअंदाज़ किया तथा गंभीर आरोपों पर कोई फॉलोअप नहीं किया। भारत का चुनाव आयोग, जिसे निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए एक निगरानी करने वाले के तौर पर काम करने की आशा की जाती है, ने भी आरोपों पर ध्यान देने की ज़हमत नहीं उठाई। आदर्श रूप से इसे इस बाबत रिपोर्ट मांगनी अथवा आरोपों की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना चाहिए था। यद्यपि यह मात्र एक घटना है जहां चुनाव आयोग प्रतिक्रिया देने में असफल रहा अथवा आदर्श चुनाव संहिता के खुले उल्लंघन की इजाज़त दी।

वे दिन चले गए जब बेलगाम राजनीतिज्ञों को चुनाव आयोग का डर होता था जो नियमों के ऐसे उल्लंघनों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। ऐसा विशेष तौर पर खौफनाक रूप से स्वतंत्र मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान हुआ जिन्होंने गंभीर कार्रवाईयों कीं, जिनमें चुनाव रद्द करना, बूथों पर कब्ज़ा करने से रोकना, नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ केस दर्ज करना तथा क़ानून का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का डर दिखाना आदि शामिल थे। कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों ने भी उद्देश्यपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि अब इसमें निरंतर गिरावट आ रही है तथा आयोग आ रही है तथा आयोग केन्द्र में सत्ताधारी पार्टी का नौकर बन गया दिखाई देता है। यहां तक कि हाल ही में समाप्त हुए चुनावों के कार्यक्रम को बनाने की योजना को लेकर भी उंगलियां उठ रहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोजित करवाने के लिए शायद ही कोई तर्क दिया गया हो। आरोप ये है कि ऐसा सत्ताधारी पार्टी को चुनाव प्रचार की सुविधा देने के लिए किया गया हो सकता है।

आयोग ने मतदान से 48 घंटे पूर्व आवश्यक तौर पर प्रचार बंद करने संबंधी नियमों के व्यापक उल्लंघन की ओर से भी अपनी आंखें मूंदें रखीं। नि:संदेह ऐसा भाजपा द्वारा अत्यंत बारीकी से किया गया, जिसे अपनी प्रचार की रणनीति अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयार करने के लिए श्रेय अवश्य दिया जाना चाहिए।

अत: प्रचार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्से के दौरान इसने रणनीतिक तौर पर एक वीडियो न्यूज़ एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक साक्षात्कार की व्यवस्था की। इसकी योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि चुनाव से एक रात पूर्व सभी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय चैनलों ने प्राइम टाइम के दौरान साक्षात्कार को प्रसारित किया। इसी रणनीति के अंतर्गत बाद में ऐसा ही एक साक्षात्कार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किया गया।

चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर चुनावों की विश्वनीयता बनाए रखने के लिए भारत को एक स्वच्छ तथा निष्पक्ष चुनाव आयोग की आवश्यकता है।

मैं स्वीकार करता हूं कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने ऐसी रणनीति का प्रदर्शन नहीं किया या संभवत: उन्हें समाचार एजेंसियों अथवा टेलिविजन चैनलों ने नज़रअंदाज़ कर दिया लेकिन तथ्य यह है कि भाजपा ने टेलिविजन चैनलों पर अनुपात के मुक़ाबले अधिक एयरटाइम का इस्तेमाल किया। आवश्यक घंटों के बाद चुनाव प्रचार को नजरअंदाज़ करने के अतिरिक्त चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि प्रचार के लिए आधिकारिक दौरों तथा समारोहों का इस्तेमाल किया गया।

जहां सरकारी स्रोतों के दुरुपयोग के मामले में भाजपा सबसे आगे रही, कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी जैसे कुछ अन्य दलों ने भी अपनी पार्टी के प्रचार अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी फंडों का दुरुपयोग किया। उदाहरण के लिए 'आप' ने पंजाब में वितरित किए गए समाचार पत्रों में दिल्ली सरकार की कार्य प्रणाली की प्रशंसा में विशाल विज्ञापन प्रकाशित करवाए। यहां तक कि पंजाब में कांग्रे सरकार ने भी सत्ता में वापस आने पर कांग्रेस सरकार के 'वायदों' का प्रमुखता से प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए ख़र्च कर डाले।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और यहां तक कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा उल्लंघनों की ओर से भी अपनी आंखें मूंदें ही रखीं। हमें याद नहीं कि हालिया अतीत में आयोग ने कोई गंभीर कार्रवाई किसी पर की हो। गत वर्ष सेवानिवृत्त नौकरशाहों तथा कूटनीतिज्ञों के एक समूह ने चुनाव आयोग ने 'इच्छाशक्तिहीन व्यवहार' पर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में कहा था कि कैसे यह संस्था 'आज विश्वसनीयता के संकट से ग्रस्त है।' चुनावों पर नागरिकों के आयोग ने भी सत्ताधारी राजनीतिक दलों द्वारा सशस्त्र बलों के दुरुपयोग के बारे में संकेत दिया। चुनाव आयोग कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी स्कैनर के नीचे आ गया जब इसने न्यायिक आदेशों के बावजूद सुरक्षा नियमों का पालन किए बना राजनीतिक दलों को विशाल रैलियां आयोजित करने की इजाज़त दी।

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने गव वर्ष अप्रैल में टिप्पणी की थी कि 'अकेला चुनाव आयोग ही कोविड-19 की तरह दूसरी लहर के लिए ज़िम्मेदार था।' अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने अधिकारियों को हत्या के आरोपों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

आयोग के नैतिक अधिकार के निरंतर पतन का एक प्रमुख कारण कैबिनेट द्वारा 'चूज एंड पिक' नीति के माध्यम से की जानी चाहिए जैसा कि कुछ अन्य पदों के मामले में है जैसे कि सी.बी.आई. के निदेशक। साथ ही चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर चुनावों की विश्वनीयता बनाए रखने के लिए भारत को एक स्वच्छ तथा निष्पक्ष चुनाव आयोग की आवश्यकता है।

रोज़गार .....

जो दिखता है वही बिकता है'

ब्रांड मैनेजमेंट एक चुनौतीपूर्ण कैरिअर क्षेत्र है, जिसमें रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है। अगर आपके अंदर सौंदर्यबोध है, तो लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट आपके लिए अच्छा कैरिअर हो सकता है। भारत में जिस तरह से दिनोदिन लग्जरी मार्केट विकसित हो रहा है, उसे देखते हुए इस क्षेत्र में प्रशिक्षित रिटेल और सर्विस के प्रोफेशंनल्स के लिए मौके ही मौक़े हैं। आज का समय ऐसा है कि 'जो दिखता है, वही बिकता है।' ऐसे में सभी छोटी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की जम का ब्रांडिंग कर रही है और इन कामों को बख़ूबी अंजाम दे रहीं हैं - कंपनी की ब्रांड मैनेजमेंट टीम। ब्रांडिंग के बढ़ते इस्तेमाल ने ब्रांड मैनेजमेंट को युवाओं के लिए एक बेहतर कैरिअर विकल्प के रूप में उभारा है। इन्हीं में से एक है पीजी डिप्लोमा इन लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स जिसे करने के बाद आपके लिए कैरिअर के रास्ते खुल जाते हैं।

कोर्स का विवरण

पीजी डिप्लोमा इन लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट 16 माह का कोर्स हैं इस कोर्स के दौरान 10 माह का एकेडमिक सेशन होता है, जिसमें एकेडमिक के साथ-साथ जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। एकेडमिक सेशन के बाद छात्रों को 06 माह की इंडस्ट्री में इंटर्नशिप प्रदान कराई जाती है।

क्या है योग्यता

इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्र छात्राओं का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। साथ ही छात्रों की लग्जरी और मैनेजमेंट में दिलचस्पी भी होनी बेहद ज़रूरी होती हे। इसके अलावा वो छात्र छात्राएं, जिनकी पर्सनलटी और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है, वो इस क्षेत्र में एक सफल तौर पर अपना कैरिअर बना सकते हैं। कोई एक विदेशी भाषा की जानकारी लाभदायक साबित हो सकती है।

कहाँ मिलेंगे अवसर

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट कोर्स करने वाले छात्रों लग्जरी सेल्स एडवाइजर, विजुअल मर्चेंडाइजर, लग्जरी इवेंट प्लानर, ब्रांड हेड, ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं। फैशन और लग्जरी कंसल्टेंट या वार्डरोब मैनेजर के तौर पर भी काम पा सकते हैं ऐसा करना है विशेषज्ञों का।

करें कुछ हटकर

रिटेल में लग्जरी सेक्टर-20 प्रतिशत सालाना की दर से आगे बढ़ रही हे। यह तेजी पिछले कई सालों से जारी है। 2020 तक इस क्षेत्र में लगभग 28 लाख लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद जताई जा रही हे। ऑटोमोबाइल, ज्वैलर्स, घड़ियां, रियल एस्टेट, वाइन, ट्रैवल एंड टूरिज़्म में नए अवसर रोज़गार के लिए वरदान साबित होगा। अभी इसमें सबसे बड़ी समस्या कुशल लोगों की है क्योंकि लग्जरी ब्रांड की सर्विस का अंदाज़ा अलग होता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

विशेषज्ञों के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट अपनी तरह का अनूठा और बिल्कुल नया कोर्स है, रिटेल की ज़रूरतें बढ़ रही हैं लेकिन इसमें कुशल लोगों की बेहद कमी है। यह एक शानदार रोज़गार का क्षेत्र है जहां संभावनाओं की कमी नहीं हैं मौजूदा विश्व परिवेश को देखकर पता चलता है कि आने वाले समय में इस सेक्टर में असीम रोज़गार की संभावनाएं हैं। यह उन युवाओं के लिए एक सफल लॉचिंग पैड है, जिन्होंने अब तक कुछ न कुछ मिस कर दिया है।

वेतनमान पर एक नज़र

इस कोर्स के पूरा होने के बाद छात्रों को इंटरर्नशिप के लिए भेजा जाता है, जिसमें बतौर स्टाइपेंड 15 से 25 हज़ार रुपये मिलते हैं। कोर्स पूरा करते ही अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो शुरूआती सैलरी 40,000-50,000 रुपये के बीच हो सकती हैं अनुभव के साथ साथ सैलरी में इज़ाफा होता रहता है। इन नौकरियों में वेतन के अलावा कई तरह के इन्सेटिव और अन्य सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं।

प्रमुख संस्थान

इण्डियन रिटेल स्कूल, नई दिल्ली
www.indianrelischool.com

लग्जरी कनेक्ट बिजनेस स्कूल, गुड़गांव, हरियाणा।
www.Icbs.edu.in

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड स्टडीज, मुंबई।
www.wsmeedu.com

सिम्बायोसिस इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे
www.sims.edu

जेविर इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च एण्ड इंटरप्रेन्योरशिप, बंगलुरु, कर्नाटक।
www.xime.org ❑❑

इस्लामी दुनिया

पाकिस्तान के सियालकोट मिलिट बेस पर धमाके

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के उत्तरी शहर सियालकोट में बीते दिनों एक के बाद एक कई धमाके हुए। मीडिया में रिपोर्टस के अनुसार धमाके की आवाज़ें इतनी तेज़ थी कि इसे पंजाब प्रांत में छावनी क्षेत्र के पास तक सुना गया। बताया गया है कि यह एक गोला बारूद स्टोरेज एरिया है। धमाके के बाद एक बड़ी आग जलती हुई देखी गई। कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पाकिस्तानी सेना ने इस घटना पर अपना आधिकारिक बयान में कहा कि मिसाइल पी.एल.-15 के परीक्षण के दौरान यह हादसा हुआ।

जहाज़ से टकराकर नौका पलटी, 06 मरे

ढाका : बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाक़े में शीतलक्ष्य नदी में एक नौका के मालवाहक जहाज से टकरा जाने के कारण कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सैयदपुर अल अमीन नगर इलाके में एमवी अफसर उद्दीन नामक नौका की एमवी रूपोशी-9 नामक जहाज से टक्कर हो गयी। नौका में कम से कम 50 यात्री सवार थे। इस हादसे के बाद नौका डूब गई। दुर्घटना के बाद बांग्लादेश अंतरर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण ने नदी पुलिस, नौसेना तटरक्षक बल के साथ मिलकर इलाके में बचाव अभियान शुरू कर दिया है।

राजनीतिक दलों की घेरेबंदी में इमरान

इस्लामाबाद : विपक्षी दलों की घेराबंदी के कारण पद जाने की अशंका से घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने इस्लामिक देशों के 57 सदस्यीय संगठन (ओआईसी) के मंच से कश्मीर का राग अलापकर फिर ध्यान भटकाने की कोशिश की है। सम्मेलन में चीन के विदेशमंत्री वांग यी भी मोज़ूद थे, लेकिन चीन में उइगर मुसलमानों के दमन पर चुप ही रहे। उन्होंने मुस्लिम एकजुटता का आहवान करते हुए कहा, 'हम डेढ़ अरब मुसलमान हैं, पर कश्मीर और फलस्तीन का मुद्दा सुलझाने में असफल रहे हैं।

पाकिस्तान में शहबाज़ विपक्षी प्रत्याशी

कराची: अविश्वास प्रस्ताव के चलते पाक पीएम इमरान ख़ान की कुर्सी पर ख़तरा मंडरा रहा है। विपक्ष का दावा है कि इमरान ने अपना बहुमत खो दिया है और इसीलिए बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट और सेना के चक्कर काट रहे हैं। इस बीच विपक्ष ने शहबाज़ शरीफ़ को अपनी तरफ से पाकिस्तान के पीएम का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यदि 28 मार्च को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उनकी जगह पूर्व पीएम नवाज़ शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज़ शरीफ देश के नए पीएम बन सकते हैं।

पाक की आर्थिक कूटनीति

आठवें दशक में प्रवेश कर चुका पाकिस्तान का निर्देशित जनतंत्र अब भारत के समतावादी लोकतंत्र की उपयोगिता और परिणामों को समझने को मजबूर हुआ है। पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति में पहली बार भू-राजनीतिक और सामरिक नीति पर भू आर्थिक नीति को तरजीह देने की बात कही गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान इस समय देश को दिवालिया होने से बचाने की कड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। हाल में घोषित नई सुरक्षा नीति में कहा गया है कि सैन्य रूप से पाकिस्तान जितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था मज़बूत नहीं होगी तो वह अपनी आज़ादी और संप्रभुता की हिफाज़त नहीं कर पाएगा। नई सुरक्षा नीति में देश की अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने पर सबसे ज़्यादा ज़ोर है और अब से विदेश नीति में भी आर्थिक कूटनीति को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

दरअसल पाकिस्तान ने नई सुरक्षा नीति के ज़रिए देश की जनता और वैश्विक समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बेहतर माहौल हो और प्रशासन भी इसी के अनुरूप हो। ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय गहरे आर्थिक संकट में फंसा पड़ा है, उस पर लगातार कर्ज़ बढ़ रहा है, पड़ोसी देशों से रिश्ते तनावपूर्ण है, उसे वैश्विक आर्थिक प्रतिबंधों का वह सामना करना पड़ रहा है और 2023 में होने वाले आम चुनाव में इमरान ख़ान के सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती भी है।

भारत से विभाजित होकर अस्तित्व में आए पाकिस्तान ने लगातार राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है। तानाशाहों से अभिशप्त इस देश के लोग लगातार अपने सैन्य शासकों की सामरिक असुरक्षा की नीति के बहकावे में आते रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान खस्ताहाल और कंगाल राष्ट्र बन कर अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। आज़ादी के बाद भारत की नीति शांति और समावेशी विकास पर आधारित रही, जबकि पाकिस्तान 1950 के दशक से ही शीतकालीन सैन्य गुटों का सदस्य बन कर वैश्विक शक्तियों के सामरिक हितों का संवर्धन करने वाला माध्यम बन गया था। तब पाकिस्तान का भारत विरोध का यह तात्कालिक तरीक़ा वहां की जनता को ख़ूब रास आया और इससे सैन्य शासकों की तख़्तापलट की नीतियों को बढ़ावा मिला। इन सब में विकास, आधुनिक शिक्षा, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को दरकिनार किया जाता रहा, जिसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज़ ब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एमबीआर) के पूर्व चेयरमैन शब्बर ज़ैदी तो कह भी चूके हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। देश पर घरेलू और विदेशी कर्ज़ पचास हज़ार अरब रूपए से भी अधिक हो गया है।

संकट यहीं ख़त्म नहीं होता। माली हालत से भी बड़ा संकट पाकिस्तान की ज़मीन पर पल रहे अतिवादी संगठन है जो कानून के शासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण विभिन्न सरकारों की धार्मिक अतिवादी नीतियां रहीं हैं। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से ज़्यादा धार्मिक शिक्षा की ओर मोड़ दिया गया, जिसके बेहद ख़तरनाक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। दुनियाभर में होने वाले आतंकी हमलों के तार पाकिस्तान से जुड़ते रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना पर आतंकियों को मदद देने के आरोपों के कारण वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने से इंकार कर दिया हैं पाकिस्तान इस समय चीन के कर्ज़ जाल में फंसा है। व्यापार और सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह पर एक तरह से चीन का ही नियंत्रण हो गया है। ग्वादर में पैसे के निवेश की साझेदारी और उस नियंत्रण को लेकर चीन से पाकिस्तान का चालीस सालों का समझौता है। चीन का इसके इनक्यानवें प्रतिशत राजस्व पर अधिकार होगा और ग्वादर पोर्ट अथारिटी को महज़ नौ प्रतिशत मिलेगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान से पास अगले चालीस वर्ष तक ग्वादर पर नियंत्रण नहीं होगा।

पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं है। भारत से रिश्ते ख़राब होने से वहां रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान काफी महंगा हो गया है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। दोनों देशो के बीच व्यापार 2019 के बाद से बंद है। पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा छीन लिया था और वहां से आयात होने वाली चीज़ों पर सीमा शुल्क दो सौ प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। बदले में पाकिस्तान ने भी भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिए थे।

पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान में अशांति और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देकर खुद का संकट बढ़ा लिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पाकिस्तान के अतिवादी संगठनों का समर्थन हासिल है और इससे कट्टरपंथी और मज़बूत हुए हैं। अफग़ानिस्तान से अपने वाले लाखों शरणार्थी पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट बन गए हैं। पाकिस्तान और अफग़ानिस्तान के बीच सीमा बेहद जटिल और लंबी है। इसकी लगातार निगरानी मुश्किल काम है। इसलिए इस सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश की जा रही है, वहीं तालिबान इस बाड़ को तोड़ कर पाकिस्तान की समस्याओं को बढ़ा रहा है। एक और अहम पड़ोसी देश ईरान से भी पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हैं। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल ईरानी चरमपंथी करते हैं।

ऐसे हालात में अगर पाकिस्तान आर्थिक कूटनीति पर काम करता है, तो उसे भारत से होकर अफग़ानिस्तान और ईरान जाने वाले मार्ग को उन्नत करना होगा। पाकिस्तान भारत की अफग़ानिस्तान में मौजूदगी और ईरान से मज़बूत रिश्तों का विरोध करता रहा है। भारत ने तुर्कमेनिस्तान- अफगानिस्तान पाकिस्तान-भारत के बीच तापी गैस पाइप लाइन परियोजना के ज़रिए प्राकृतिक गैस की खरीद और बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे अमेरिका का भी समर्थन हासिल था। पर एक दशक बीत जाने के बाद भी यह योजना अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है और इसका एक बड़ा कारण पाकिस्तान की भारत विरोधी नीतियां रहीं हैं। यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के दौलताबाद गैस फील्ड से शुरू होकर अफग़ानिस्तान के हेरात- कंधार से होते हुए पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान पहुंचेगी तथा गैस पाइपलाइन भारत-पाकिस्तान सीमा के फजिल्का में ख़त्म होगी। ज़ाहिर है, इसका लाभ भारत, पाकिस्तान और अफग़ानिस्तान के करोड़ों लोगों को मिल सकता है लेकिन पाकिस्तान के अतिवादी संगठन अपने मुल्क के रास्ते भारत को मिलने वाली मदद का विरोध करते रहे हैं और उनके आगे सरकार लाचार है।

पाकिस्तान ने नीतियों में बदलाव की बात तो की है, लेकिन लोकतंत्र की अनिश्चितता और अस्थिरता से आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलना असंभव है। इसके साथ ही समावेशी विकास के लिए प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व, औचित्य और समता की दृष्टि से भी देश में अभी बहुत कुछ सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक सुधार की ज़रूरत है। इन सब चुनौतियों के बीच अगर पाकिस्तान आर्थिक सहयोग बढ़ाने की नीति पर आगे बढ़ता है तो यह उसके लिए ही नहीं, भारत के लिए भी लाभकारी हो सकता है। यदि, पाकिस्तान अपनी नई सुरक्षा नीति के अनुरूप क्षेत्रीय देशों से अच्छे रिश्ते क़ायम करने की इच्छाशक्ति दिखाता है तो यह दक्षिण एशिया समेत पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत होंगे।❑❑

भारत से विभाजित होकर अस्तित्व में आए पाकिस्तान ने लगातार राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है। तानाशाहों से अभिशप्त इस देश के लोग लगातार अपने सैन्य शासकों की सामरिक असुरक्षा की नीति के बहकावे में आते रहे। यही कारण है कि पाकिस्तान खस्ताहाल और कंगाल राष्ट्र बन कर अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। आज़ादी के बाद भारत की नीति शांति और समावेशी विकास पर आधारित रही, जबकि पाकिस्तान 1950 के दशक से ही शीतकालीन सैन्य गुटों का सदस्य बन कर वैश्विक शक्तियों के सामरिक हितों का संवर्धन करने वाला माध्यम बन गया था। तब पाकिस्तान का भारत विरोध का यह तात्कालिक तरीक़ा वहां की जनता को ख़ूब रास आया और इससे सैन्य शासकों की तख़्तापलट की नीतियों को बढ़ावा मिला। इन सब में विकास, आधुनिक शिक्षा, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को दरकिनार किया जाता रहा।

संजीय पांडेय

म्यांमा में लोकतंत्र दूर की कौड़ी

म्यांमा में लोकतंत्र की बहाली को लेकर अनिश्चितता के बादल और गहराते जा रहे हैं। इस मुल्क में लोकतंत्र बहाल होगा भी या नहीं और होगा तो कब तक, ये ऐसे प्रश्न हैं जो न सिर्फ एशियाई देशों बल्कि पश्चिम देशों के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं हालांकि यहां के सैन्य शासकों के अब तक के रुख़ से तो यही लग रहा है कि म्यांमा में लोकतंत्र की वापसी आसान नहीं है। पिछले दिनों भारत के विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला म्यांमा के सरकारी दौरे पर गए थे। म्यांमा में पिछले वर्ष फरवरी में निर्वाचित सरकार के तख्तापलट के बाद किसी भारतीय विदेश सचिव का यह पहला दौरा था। इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव ने जेल में बंद नेता आंग सान सू की से मुलाक़ात करने के लिए म्यांमा के सैन्य शासन से इजाज़त मांगी थी। पर उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी गई। म्यांमा के सैन्य शासकों का यह रुख़ काफी कुछ संकेत देता है।

श्रृंगला की म्यांमा यात्रा दबाव की कूटनीति के लिहाज़ से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि इसके नतीजों को लेकर फिलहाल कोई अनुमान लगाना जल्दबाज़ी होगी। भारतीय विदेश सचिव की यह यात्रा पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते उग्रवाद और चीन के परोक्ष दख़ल के मद्देनज़र भी महत्वपूर्ण थी। भारत ने म्यांमा में लोकतंत्र बहाली के लिए सैन्य शासकों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। म्यांमा प्रशासनिक परिषद के साथ हुई बैठक में श्रृंगला ने कई अहम मुद्दों पर बात की। इस बैठक में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती उग्रवादी गतिविधियों और म्यांमा की सीमा में शिविर बनाए बैठे उग्रवादी संगठनों का मुद्दा खासतौर से उठा था। हालांकि भारत की चिंताओं पर म्यांमा कितना गंभीर होगा, यह चीन पर निर्भर करता है क्योंकि इस समय म्यांमा का सैन्य प्रशासन पर पूरी तरह से चीन के प्रभाव में है।

देश में लोकतंत्र बहाली को लेकर म्यांमा के सैन्य शासक कोई भी बाहरी दबाव मानने के तैयार नहीं है। वे संयुकत राष्ट्र और अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। चीन और म्यांमा के सैन्य शासकों के बीच एक समझौता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के हितों का ख़्याल रख रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव म्यांमा के दूसरे पड़ोसी देशों पर पड़ रहा है। चीन का भय इस क़दर है कि आसियान सहित कई अन्य देश म्यांमा को लेकर सतर्कता के साथ क़दम उठा रहे हैं। म्यांमा में लोकतंत्र के खात्मे का सीधा असर भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड पर पड़ा है। लोकतंत्र समर्थकों पर सैन्य दमन बढ़ने के कारण भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड में लोग शरण लेने को मजबूर हुए थे। म्यांमा की सेना आज भी लोकतंत्र समर्थकों के साथ हिंसक व्यवहार कर रही हैं देशभर में जिस तरह से लोकतंत्र समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है और आंदोलनों को कुचला जा रहा है, वह पूरी दुनिया देख रही है।

म्यांमा के साथ भारत की लगभग सत्रह सौ किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भारत की चिंता यह भी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों ने म्यांमा में जो अड्डे बना रखे हैं, उन्हें म्यांमा की सेना गुपचुप मदद दे रही है और ऐसा वह चीन के इशारे पर कर रही है। कुछ समय पहले मणिपुर में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के एक अधिकारी सहित कुछ जवान शहीद हो गए थे। माना जा रहा है कि इस हमले के लिए ज़िम्मेवार उग्रवादी संगठन के लोग म्यांमा के इलाक़े में हैं।

अपने इस दौरे में भारतीय विदेश सचिव ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की। म्यांमा में लोकतांत्रिक सरकार के तख़्लापलट में चीन की परोक्ष भूमिका रही है। दरअसल इस वर्ष फरवरी में लोकतांत्रिक सरकार के तख़्लापलट से पहले म्यांमा सेना के मुखिया मिन आंग लेंग और चीन सरकार के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी की मुलाक़ात हुई थी। बताया जाता है कि इसी मुलाक़ात में तख़्तापलट को लेकर चीन ने सहमति दी थी। यही कारण है कि म्यांमा वैश्विक दबाव की परवाह नहीं कर रहा है और आंग सान सू की को जेल में बंद कर रखा है। एक मामले में उन्हें सज़ा भी सुना दी गई है। भारत इस हक़ीक़त से अंजान नहीं है कि म्यांमा की तत्कालीन एनएलडी की सरकार से चीन नाखुश था। इसके मूल में कारण चीन के आर्थिक हित थे। एनएलडी की सरकार म्यांमा में प्रस्तावित चीनी निवेश योजनाओं से सहमत नहीं थी। विभिन्न निवेश योजनाओं में मिलने वाले चीनी कर्ज़ को लेकर एनएलडी की सरकार सावधान थी। उसे डर था कि म्यांमा चीनी निवेश के बहाने कर्ज़ के जाल में फंस जाएगा। एनएलडी सरकार के विरोध के कारण ही प्रस्तावित चीनी परियोजनाओं में कटौती की गई। चीन-म्यांमा आर्थिक गलियारे में प्रस्तावित कुल अड़तीस योजनाओं में से सिर्फ नौ योजनाओं पर एनएलडी की तत्कालीन लोकतांत्रिक सरकार ने सहमति जताई थी। ऐसे में चीन कैसे एनएलडी की निर्वाचित सरकार को बर्दाश्त कर पाता?

बेशक म्यांमा के सैन्य शासक चीन के उद्देश्यों में सहयोग दे रहे हैं, पर म्यांमा की जनता चीन के उद्देश्यों को समझ रहे हैं और इसीलिए उसका विरोध कर रही है चीन म्यांमा के प्राकृतिक संसाधनों का जम कर दोहन कर रहा हैं। इससे स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। चीनी परियोजनाओं के कारण म्यांमा में विस्थापन की समस्या और गंभीर हो गई है। कचीन राज्य में लोगों ने चीन के सहयोग से प्रस्तावित मैत्सोन जल बिजली परियोजना का विरोध किया था, जिस कारण इस परियोजनों को रद्द करना पड़ गया था। इसलिए चीन चाहता है कि म्यांमा में सैन्य सरकार बनी रहे और विरोध करने को कुचलती रहे।

लेकिन अब सैन्य शासन आने के बाद चीन-म्यांमा आर्थिक गलियारा का काम ज़ोरों पर है। यह आर्थिक गलियारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की तर्ज़ पर विकसित किया जा रहा है। चीन म्यांमा आर्थिक गलियारा चीन को हिन्द महासागर में सैन्य विस्तार में काफी मदद देगा। इसके तहत म्यांमा में रेल नेटवर्क खड़ा किया जाना हैं प्रस्तावित रेल नेटवर्क से देश के भीतर विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़े जाने का प्रस्ताव है। गलियारे की एक महत्वपूर्ण योजना म्यांमा के रखाइन प्रांत स्थित क्याकप्यू बंदरगाह का विकास भी है। यह बंदरगाह भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो भविष्य का ग्वादर बनेगा। पाकिस्तान में बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह अब पूरी तरह से चीन के कब्ज़े में है। ग्वादर बंदरगाह पर चीन की मौजूदगी को सुरक्षित करने के लिए स्थानीय नागरिकों पर तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग इन प्रतिबंधों के कारण सरकार के कारण सरकार के ख़िलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अगर चीन म्यांमा के क्याकप्यू बंदरगाह को विकसित करने में सफल हो गया तो भविष्य में इसका नुकसान भारत को होगा ही, म्यांमा भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। चीन इस बंदरगाह के जरिए हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाएगा। एक ओर चीन क्याकप्यू बंदरगाह के रास्ते तेल और गैस आयात करने की योजना बना रहा है, तो दूसरी ओर उसका उद्देश्य भारतीय समुद्री सीमा को घेरना भी है।

बेशक म्यांमा के सैन्य शासक चीन के उद्देश्यों में सहयोग दे रहे हैं, पर म्यांमा की जनता चीन के उद्देश्यों को समझ रहे हैं और इसीलिए उसका विरोध कर रही है चीन म्यांमा के प्राकृतिक संसाधनों का जम कर दोहन कर रहा हैं। इससे स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। चीनी परियोजनाओं के कारण म्यांमा में विस्थापन की समस्या और गंभीर हो गई है। कचीन राज्य में लोगों ने चीन के सहयोग से प्रस्तावित मैत्सोन जल बिजली परियोजना का विरोध किया था, जिस कारण इस परियोजनों को रद्द करना पड़ गया था। इसलिए चीन चाहता है कि म्यांमा में सैन्य सरकार बनी रहे और विरोध करने को कुचलती रहे।

भारत और म्यांमा का संबंध सदियों पुराना है। इसका आधार दोनों देशों की सभ्यता और संस्कृति हैं म्यांमा में बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। यहां की 88 प्रतिशत आबादी बौद्ध है। लेकिन यहां अल्पसंख्यक मुसलमान शुरू से ही बौद्धों और सेना के निशाने पर रहे है। म्यांमा में होने वाली इस जातीय और धार्मिक हिंसा का सीधा प्रभाव भारत पर पड़ता है। ऐसी हिंसा का ही नतीजा है कि आज हज़ारों रोहिंग्या शरणार्थी भारत में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में अगर म्यांमा में चीन सीधे तौर पर मज़बूत होगा तो भारत के लिए हालात उतने ही चुनौतीपूर्ण होंगे।❑❑

ख़ास ख़बरें

श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के सुरक्षा बलों के हवाले

कोलंबो : श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारों में अपनी बारी की बाट जोहते हुए 70 वर्ष के दो बुज़ुर्गों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। श्रीलंका इन दिनों ईंधन की भारी किल्लत और आर्थिक अव्यवस्था से जूझ रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों करीब छह घंटों से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इस घटना के बाद पैट्रोल पम्पों पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है।

बेल्जियम में 'कार्निवाल' में लोगों को तेज़ रफ्तार कार ने रौंदा 6 की मौत

ब्रसेल्स : दक्षिणी बेल्जियम के एक छोटे से शहर में 'कार्निवाल' (सार्वजनिक समारोह) में मस्ती कर रहे लोगों को एक कार ने टक्कर मार दी जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 2 दर्जन व्यक्ति घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रसेल्स से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्ट्रेपी ब्रेकेग्नीज शहर में समारोह के लिए इकट्ठा हुई भीड़ में एक व्यक्ति ने कार घुसा दी। इस दौरान पुलिस कार का पीछा कर रही थी।

अमरीका में हेलिकॉप्टर दुर्घटना, 05 घायल

अजूसा (अमेरिका) : अमरीका के अजूसा शहर के निकट एंजिलिस राष्ट्रीय उद्यान में पिछले दिनों लॉस एंजिलिस शेरिफ के एक हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पांच लोग घायल हो गए। शेरिफ एलेक्स विलनुएवा ने 'लॉस एंजिलिस टाइम्स' को बताया कि सभी पांच यात्रियों को पोमोना वैली मेडिकल सेंटर ले जाया गया। यात्रियों में से एक की हालत गंभीर है, दो की हालत बेहतर और दो अन्य को मामूली चोटें आई।

किराये की कोख से पैदा हुए बच्चों का है मां-बाप का इंतज़ार

कीव : यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बम रोधी आश्रय स्थल में किराये की कोख से जन्मे कम से कम 20 बच्चे अपने विदेशी माता-पिता के युद्धाग्रस्त देश में आने और उन्हें ले जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जन्मे इन बच्चों की अच्छी देखभाल हो रही है, लेकिन बेसमेंट में रहने के बावजूद उन्हें समय-समय पर होने वाली गोलीबारी की आवाज़ साफ सुनाई देती है। सरोगेसी केन्द्रों की कई नर्सें भी आश्रय स्थल में ही रह रही है क्योंकि उनके लिए रोज़ाना घर आना-जाना बहुत ख़तरनाक है। कीव पर कब्ज़े की कोशिशों में जुटे रूसी बलों को यूक्रेनी जवान कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिलहाल इस युद्ध से इन नवजात शिशुओं के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लग गया है।

इस्लाम अमनो सकून का ऐसा दरिया है जो सबके लिए है

आज आलमी सतह पर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा और कट्टरवाद के आरोप लगाये जा रहे हैं और उनको साबित करने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं यूरोपीय मीडिया की बराबर ये कोशिश रहती है कि मामूली मामूली घटनाओं को जो आम हैसिअत रखती है और जिनसे समाज का कोई भी वर्ग बचा हुआ नहीं है। खूब बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जाये और इनको इस्लाम से जोड़कर इस्लाम और उसकी शिक्षाओं को मलामत का निशाना बनाया जाये जबकि सच्चाई ये है कि इस्लाम अमन का मज़हब है और इसमें इंसानी हुकूक़ का जितना सम्मान है उतना किसी भी धर्म में नहीं है। लफ़्ज़ इस्लाम अमन व सलामती से ताबीर है और मज़हब इस्लाम अखवत भाईचारगी, तौहीद व रिसालत, न्याय इत्तेहाद व इत्तेफाक़, अज्ज़ व इनकसारी सब्र व हलम अफ़ू व दरगुज़र, अख़्लाक़ व किरदार तकवा व परहेज़गारी, अमानतदारी व दयानतदारी, रास्ती मामलात और सरापा इंसानियत का महवर है। वह अपने मानने वालों को महफ़ूज़ करता है। इस्लाम अमनो सकून का ऐसा दरया है जो अकवाम आलम के खुश्क मुजतरिब और मुज़्माहिल कुलूब को सैराब व शादाब करता है, इसकी पुर तासीर सदाये सहराओ बयाबानों और कोहसारों की चीरती हुये जब बहरे जुलमात में गौते लगाती है तो गुमराही व तारीकी राहें फरार हासिल करती है और अंधेरा रोशनी में बदल जाता है।

इस्लाम एक ऐसा चश्मा है जो सिर्फ मुसलमानों के लिये ही ख़ास नहीं है बल्कि हर उस शख़्स के लिये मज़हबे इस्लाम में रूहानी तमद्दुनी खजाने छिपे हुये हैं जो इससे फायदा उठाने की सलाहियत रखता है, वह इससे फायदा है वह इस्लाम ही तो था जिसने शहनशाहियत की कदीम और बोसीदा दीवारों को तोड़ डाला। इस्लाम ने ही गुलामों को गुलामी की जंज़ीरों से आज़ाद कराकर इनके सिरों पर शहनशाहयत का ताज रख दिया और शहंशाहों को अवाम का खिदमतगार बना दिया। इस्लाम ने समाज में व्यक्तिगत आज़ादी की अहमियत को सामने रखते हुये इनकी ज़िन्दगी, अमलाक और जायज़ मुसर्रतों की बक़ा और हिफाज़त की पूरी-पूरी ज़मानत दी है।

अगर इस्लाम का तकाबुली मुताला किया जाये तो पता चलेगा कि दुनिया के तमाम अदयान कुछ और [illegible] है और ज़िन्दगी गुज़ारने के विभिन्न तरीक़ों में वह देश व समाज के बनाये हुये कानूनों के मोहताज हैं लेकिन इस्लाम ने हयाते इंसानी का कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जहां इसकी वाज़ेह हिदायात न हो, इस्लाम ने ही ये ऐलान किया था कि तुम अपनी बेटियों को ज़िन्दा दफन न करो और इसी पर बस नहीं किया बल्कि जाते हरीम को मुआशी आज़ादी और बराहे रास्त समाजी ज़िन्दगी में हिस्सेदार बनाया। मज़हबे इस्लाम ने औरतों के जो अधिकार तय करें है और उनको विभिन्न शक्लों में जो इज्ज़त बख़्शी है वह किसी से कम नहीं।

इस्लाम का अखवत व मसावात का तसव्वुर अज़्मतों शराफत की बहुत बड़ी ज़मानत है, इसलिये कि इसके अनुसार सब इंसान बराबर है, रंग व नस्ल, जात बिरादरी की बुनियाद पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। इस्लाम की नज़र में किसी को अगर दूसरे पर फज़ीलियत हासिल है तो वह सिर्फ इस बुनियाद पर कि वह अपने ख़ालिक़ व मालिक से कितना डरे और खुदा को कितना करीब रखता है। इस हक़ीक़त को क़ुरआन पाक ने इस तरह बयान किया है :-

''ऐ लोगों! हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें गिरोहों और कबीलों में इसलिये बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, बेशक तुम में सबसे ज़्यादा क़ाबिले इज्ज़त वह है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। (सूरे हजरात)

इस्लाम मज़हब जंगो जिदाल और क़त्लोगारतगरी का सख़्त विरोध करता है। कुरआन पाक में एक शख़्स के क़त्ल को सारे इंसानों का क़त्ल कहा गया है और नाहक़ क़त्ल करने वाले के लिये सज़ाये मौत मुक़र्रर की है। कुरआन पाक में इरशाद होता है।

''जिसने किसी इंसान को खून के बदले में या ज़मीन पर फसाद फैलाने (की सज़ा) के अलावा और किसी वजह से क़त्ल किया तो गोया इसने सारे इंसानों का क़त्ल किया और जिसने किसी की जान बचाई तो इसने गोया तमाम इंसानों को ज़िन्दगी दी। (अलमायदा)

क़ुरआन पाक के इन अहकामात पर जनाब रसूलुल्लाह सल्ल॰ ने इस तरीक़े पर अमल किया कि रहती दुनिया तक इसकी नज़ीर नहीं मिलती। आहंज़रत सल्ल॰ के बाद इस मादरे गीती पर बहुत से ऐसे मुहद्दीसीन वाईजीन, सलातीन इस्लाम पैदा हुये हैं जिन्होंने अपनी कोशिश और खुलूसनियती से इस्लाम की शगुफ्ता कली को तरोताज़ा कर दिया।

हज़रत उमर बिन आस इस्लाम के एक जलीलुलक़द्र फरजंद सिपाही व सिपहसालार थे उन्होंने कैसरे रोम को शकस्त दी थी। सन 64 हिजरी में मिस्र पर हमला करके इस्कंदरिया को जीता था। इस्कंदरिया को फतेह करने के बाद इस मर्दे मुजाहिद और सहाबिये रसूल ने सिर्फ ये ऐलान फरमाया कि हर शख़्स को अपनी मज़हबी रसूमात की अदायगी की आज़ादी होगी और इनकी तमाम इबादतगाहों की हिफाज़त की जायेगी। मुसलमान इनकी जान-माल और इज्ज़त व आबरु की रक्षा करेंगे। हज़रत उमरु बिन आस के इस ऐलान पर शुरू में तो इसाईयों को यकीन नहीं आया मगर जब इनका क़ौल व अमल दोनों समान देखें तो मुसलमानों के अदल व इंसाफ़ पर भरोसा करने लगे और इनके दिमागों से फतह और मफतूह का फर्क बिल्कुल जाता रहा और इन्हें इस्लाम की आलाकदरों पर रश्क आने लगा। इसी तरह सुलतान सलाउद्दीन अयूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस पर दोबारा कब्ज़ा किया तो इन इसाईयों से कोई बदला नहीं लिया जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की फतेह के वक़्त हज़ारों मुसलमानों को क़त्ल कर दिया था बल्कि इसके विपरीत उनके साथ इस्लामी हमियत और मुहबबत का ऐसा मामला फरमाया, वहां के नागरिक सलाउद्दीन अय्यूबी पर गर्व करने लगे एक सलाहुद्दीन अय्यूबी पर ही क्या मौक़ूफ है सभी सलातीन और बेशतर शासकों का यही किरदार रहा है।

इन संक्षिप्त दलायल की रोशनी में हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि इस्लाम अमन सलामती इत्तेहाद और इत्तेफाक़ का पयाम्बर है। जुल्म बर्बरता और इफतराक व इन्तशार का दाई नहीं। इस तरह तारीख़ इस्लाम का मुताला करने के बाद हम बिला खौफ़ व तरदीद कह सकते हैं कि इस्लामी तहज़ीब आपसी मतभेदों को घटाकर एक दूसरे को करीब लाने की दावत देती है और दुनिया को क़त्लो ग़ारतगरी की आमाजगाह बनाने के बजाये अमन, सलामती और खुशहाली का गहवारा बनाने की दावत देती हैं इस्लामी तारीख़ी हकायक को पढ़ने के बाद हम यकीनन इस बात को मानने के लिये तैयार होंगे कि इस्लाम के तहज़ीबी व तमद्दुनी आईने में सूरज की चमकती हुई पेशानी और चांद का हंसता हुआ चेहरा अपनी सारी सिफात के साथ मौजूद है।

जहां तक मीडिया और इस्लाम दुश्मन ताक़तों के प्रचार का सवाल है तो इससे हरासा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम के ख़िलाफ़ ये यूरिश कोई नहीं है पिछले 14 सौ सालों से यह सिलसिला जारी है और हक़ को दबाने की हर कोशिश आगे भी जारी रहेगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ग़ैर इस्लामी तरीक़ों से तौबा कर ले, यही एक कारगर नुस्खा है जो न सिर्फ हमारी तरक्क़ी का ज़ामिन है बल्कि इस्लाम और मुसलमान दोनों को आलोचना का निशाना बनाने वालों के लिये एक सही और मज़बूत जवाब साबित हो सकता है। ❑❑

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल बक़रा नं॰ 02)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

और वे लोग रास्ता पाने वाले नहीं हुए।

अर्थात् मुनाफिक़ों ने प्रत्यक्ष ईमान स्वीकार किया और दिल में इंकार रखा जिसके कारण आख़िरत में ख़राब और दुनिया में अपमानित हुए क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब में उनकी दशा सब पर खोल दी। ईमान लाते तो दोनों जहान में सम्मानित होते। उनकी तिजारत (व्यापार) ने उन को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, न दुनिया के हिसाब से और न आख़िरत के हिसाब से और वे सब कुछ न समझ सके। केवल तथाकथित ईमान को लाभदायक समझकर इस ख़राबी और अपमान में फंस गये। ये सब आगे आयत में उन मुनाफिक़ों की दशा के अनुकूल दो उदाहरणों का वर्णन किया जाता है।

उनका उदाहरण उस व्यक्ति जैसा है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके आसपास को प्रकाशित कर दिया तो अल्लाह ने उनके प्रकाश को छीन लिया और उनको अंधेरे में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते।

अर्थात् मुनाफिक का उदाहरण ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जंगल में रास्ता देखने के लिए घोर अंधेरी रात में आग जलाये और जब आग जल गयी और रास्ता दीखने को हुआ तो अल्लाह ने उस आग को बुझा दिया और वह व्यक्ति अंधेरी रात के कारण जंगल में खड़ा रह गया कि कुछ दिखाई नहीं देता ऐसे ही मुनाफिक़ों ने मुसलमानों के भय के कारण कलमे के प्रकाश से काम लेना चाहा और कुछ ही लाभ उठाने पाये थे (जैसे जान माल की रक्षा) कि कलमे का प्रकाश और लाभ सब नष्ट हो गया, यह उनके कपट का परिणाम हुआ और मरते ही अल्लाह की यातनाओं में फंस गये।

बहरे हैं गूंगे है अंधे, सो वे लोग नहीं लौटेंगे।

अर्थात् बहरे हैं जो सच्ची बात नहीं सुनते, गूंगें हैं जो सच्ची बात नहीं कहते, अंधे हैं जो अपने लाभ हानि को नहीं देखते, जो व्यक्ति बहरा भी हो और गूंगा भी हो वह किस प्रकार रास्ते पर आये, केवल अंधा हो तो वह किसी को पुकारे या किसी की बात सुनें इसलिए कदापि आशा नहीं कि पथभ्रष्टता से सन्मार्ग की ओर लौटे।

या उनका उदाहरण ऐसा है जैसे आसमान से ज़ोर का मेह पड़ रहा हो उसमें अंधेरे भी हों और गरज और बिजली भी। कड़क के मारे मौत के भय से अपने कानों में उंगलियां ठूंसे देते हैं और अल्लाह इंकारियों को घेरे में लिए हुए है।

दूसरी उपमा मुनाफिक़ों की उन लोगों जैसी है जिन पर भारी वर्षा हो रही हो और उस वर्षा में भिन्न-भिन्न प्रकार की अंधियारी हो जैसे बादल भी बड़े घने हों, वर्षा मूसलाधार हो रही हो और रात भी अंधेरी हो और गहन अंधकार के साथ बिजली की कड़क और चमक भी ऐसी भयानक हो कि वे लोग मौत से कानों में उंगलियां देते हों कि कहीं आवाज़ की कठोरता से दम न निकल जाये। इसी प्रकार मुनाफिक़ धर्म के आदेश और चेतावनियों को सुनकर और अपने तिरस्कार और अपयश को देखकर और संसार के लाभों का विचार करके अनोखी उलझन और भय व परेशानी में फंसे हैं और अपनी निरर्थक उपायों से अपना बचाव करना चाहते हैं लेकिन अल्लाह की क़ुदरत और शक्ति उनको चारों ओर से घेरे है। अल्लाह की पकड़ और अज़ाब से वे अपना बचाव नहीं कर सकते।

रुकू नं॰ 2

समीप है कि बिजली उनकी आंखें उचकले, जब उन पर बिजली चमकती है तो उसके प्रकाश में चलने लगते हैं और जब अंधेरा होता है तो खड़े रह जाते हैं और यदि अल्लाह चाहे तो उनके कान और आंखें छीन ले नि:संदेह अल्लाह प्रत्येक वस्तु पर अधिकारी है।

सारांश यह है कि मुनाफिक़ लोग अपनी पथपृष्टता और अंधविश्वासों में फंसे हैं लेकिन जब इस्लाम का प्रभुत्व और बड़ा चमत्कार देखते हैं और इस्लाम की ओर से चेतावनी सुनते हैं तो दिखावे को इस्लाम की ओर झुकते हैं और जब कोई दुनिया की तकलीफ और कठिनाई दीख पड़ती है तो इंकार पर अड़ जाते हैं। जैसे तेज़ वर्षा और अंधकार में बिजली चमकी तो पांव बढ़ा लिया, फिर खड़े हो गये, लेकिन अल्लाह को तमाम वस्तुओं का ज्ञान है और उसकी क़ुदरत से कोई वस्तु बाहर नहीं तो ऐसे बहानों से क्या काम निकल सकता है?

तमिलनाडु

द्रविड़ राजनीति के लिए नए सबक़

दशकों से तमिलनाडू की सत्ता पर काबिज़ द्रमुक और अन्नाद्रमुक का आधार द्रविड़ विचारकों की सामाजिक न्याय की अवधारणा रही है। यहां वर्ष 1967 में कांग्रेस सरकार का अंत हुआ था, जिसके बाद से द्रविड़ विचारधारा और कल्याणकारी राज्य संबंधी नीतियों का संगम ही मतदाताओं को लुभाता रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भाजपा के हाथों समाजवादी पार्टी की हार ने हिन्दुत्व की ताक़त से मुक़ाबला करने की संयुक्त ओबीसी की सीमा को संभवत: उजागर कर दिया हैं मगर तमिलनाडू में कहानी बिल्कुल अलग है।

यहां लोगों को ग़ैर द्रविड़ विकल्प मुहैया कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने सालों से कई प्रयास किए हैं। मगर यह कवायद जमीन पर सफल नहीं हो सकी है। इसीलिए, द्रविड़ विचारधारा आज भी निर्विरोध क़ायम है। इसके उलट, राज्य के अन्य दल द्रविड़ विचार धारा के नकलची या घटिया प्रतिरूप बनकर रह गए हैं। यहां के वामपंथी दल भी इसके अपवाद नहीं हैं। 1980 के दशक के अंत में वीपी सिंह और लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी ताक़त के बूते हिन्दुत्व की लहर पैदा करने की कोशिशों को नाकाम किया था। 23 अक्तूबर 1990 को लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके उनकी रथयात्रा बाकायदा रोक दी थी। इससे पहले वीपी सिंह पिछड़ी जातियों के मतों के बूते ही प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाए थे।

इस बार मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतों को एकजुट करने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उन्होंने गठबंधन बनाने के लिए ग़ैर यादव, ग़ैर जाटव दलितों और अन्य अति पिछड़े समुदायों को साथ लाने का प्रयास किया। उन्होंने किसान जैसे विभिन्न हित समूहों को भी अपने साथ जोड़ा। मुस्लिमों को पर्याप्त टिकट बांटें। मगर उनके तमाम प्रयास सफल न हो सके।

इस बार मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतों को एकजुट करने के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया। उन्होंने गठबंधन बनाने के लिए ग़ैर यादव, ग़ैर जाटव दलितों और अन्य अति पिछड़े समुदायों को साथ लाने का प्रयास किया। उन्होंने किसान जैसे विभिन्न हित समूहों को भी अपने साथ जोड़ा। मुस्लिमों को पर्याप्त टिकट बांटें। मगर उनके तमाम प्रयास सफल न हो सके। तो क्या इसका अर्थ यह है कि सिर्फ सामाजिक एकता भगवा लहर को मात नहीं दे सकती?

प्रश्न यह भी है कि क्या तमिलनाडू में द्रमुक के लिए इसमें कोई सबक़ है? भाजपा बरसों से राज्य की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। बेशक, उसको अब तक बहुत सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले मैदान में उतरने के बावजूद उसके वोट प्रतिशत में करीब छह प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व सफलता ने तमिलनाडू में भाजपा कार्यकर्ताओं और उसके समर्थकों का उत्साह बढ़ा दिया है। इसका मुक़ाबला द्रमुक पार्टी आख़िर कैसे करेगी? द्रविड़ विचारधारा की सफलता के कई कारण हैं। बेशक, ओबीसी मतों की एकजुटता इस आंदोलन का आधार है, फिर भी कई ऐसे अन्य कारक है, जो इसे एक अजेय राजनीतिक मंच बनाते हैं। ये स्वाभिमान आंदोलन नहीं है, जिनसे सामाजिक परिवर्तन हुए। मध्याह्न भोजन, एक रुपये किलो चावल व अन्य नई योजनाओं ने न केवल यहां के पोषण में सुधार किए, बल्कि स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का काम भी किया। शिक्षा पर लगातार ध्यान दिए जाने से कुशल कार्य बल बना, जिसने निर्माण कार्य और सेवा, दोनों ही मामलों में उद्योगों की मदद की।

यहां स्वास्थ्य देखभाल और ग़रीबों के लिए घर जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं ने न केवल सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि की और कई सामाजिक संकेतकों में राज्य को शीर्ष पर पहुंचाया, बल्कि इसने राज्य की माली हालत सुधारने में भी मदद की। सरकार और सत्तारुढ़ दल ने मिलकर काम किया, ताकि समाज के अन्तिम छोर तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों को मिले। हालांकि, मुफ्त टेलीविजन, मिकसर ग्रांइडर, जैसे कुछ लोक लुभावन योजनाओं की अर्थशास्त्रियों के एक तबक़े ने तीखी आलोचना भी की, लेकिन मुफ्त की ऐसी योजनाएं वास्तव में कई आम लोगों का जीवन बदलने में सफल रही हैं।

यहां की राजनीति का सिनेमा से भी हमेशा करीबी रिश्ता रहा है। बुद्धिजीवी इस पर नाक भौं भले सिकुड़ते रहे हों, मगर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि द्रविड़ नेता जनता के साथ संवाद करने के लिए सिनेमा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना जानते हैं। द्रविड़ विचारक जनसंचार के विस्फोट से बहुत पहले इस माध्यम के तहत्व को जान गए थे। इसीलिए, राज्य की तमाम पार्टियां फिल्म की ताक़त से परिचित हैं। यहां तक कि भाजपा ने भी, जो वैचारिक पक्षधरता की क़समें खाती रहती है, सुपरस्टार रजनीकांत की मदद से 2016 में राज्य की राजनीति में प्रभावी ढंग से प्रवेश करने का प्रयास किया था, मगर 2021 में उसे इससे पीछे हटना पड़ा, क्योंकि रजनीकांत ने सक्रिय राजनीति में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। तब से पार्टी राज्य में खुद को फिर से स्थापित करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाए हुए हैं। यह ज़मीन पर लगातार काम कर रही है, ताकि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और प्रबंधकों का एक नेटवर्क बना सके। राज्य के छोटे छोटे सामाजिक समूहों के साथ गठबंधन बनाने की भी यह कोशिश कर रही हैं स्थानीय नेताओं को

बाक़ी पेज 11 पर

सरकार और सत्तारुढ़ दल ने मिलकर काम किया, ताकि समाज के अन्तिम छोर तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों को मिले। हालांकि, मुफ्त टेलीविजन, मिकसर ग्रांइडर, जैसे कुछ लोक लुभावन योजनाओं की अर्थशास्त्रियों के एक तबक़े ने तीखी आलोचना भी की, लेकिन मुफ्त की ऐसी योजनाएं वास्तव में कई आम लोगों का जीवन बदलने में सफल रही हैं।

जब देश की बहू 'स्वेतलाना' को नहीं मिल सकी थी भारत में शरण

सुरेन्द्र किशोर

वर्ष 1959 में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने दलाई लामा को भारत में शरण दे दी थी। किन्तु प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने सन 1966 में स्टालिन की बेटी 'स्वेतलाना' को यहां शरण नहीं दी, जबकि 'स्वेतलाना' भारत की बहू थीं। इस तरह इंदिरा गांधी ने भावना पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अधिक ध्यान दिया था उन्हें आशंका थी कि स्वेतलाना को शरण देने से सोवियत संघ से भारत के संबंध हो सकता हैं। दूसरी ओर, जवाहर लालनेहरू तिब्बत में चीनी ज़्यादतियों की ख़बरों से भावुक हो गए थे और उन्होंने दलाई लामा और उनके अनुयायियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई थी।

आज की पीढ़ी के कम ही लोग यह जानते होंगे कि सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन की बेटी 'स्वेतलाना' भारत की बहू थीं। उनके पति ब्रजेश सिंह के असामयिक निध न के बाद उनकी अस्थि भस्म लेकर वह भारत आई थीं। पूर्ववर्ती कालाकांकर राज्य के राजा दिनेश सिंह ब्रजेश सिंह के भतीजे थे। दिनेश सिंह पहले जवाहर लाल नेहरू के निजी सचिव थे। बाद में वे केन्द्रीय मंत्री बने। स्वेतलाना यहीं बसना चाहती थीं। पर क्योंकि सोवियत संघ ऐसा नहीं चाहता था उन दिनों लियोनिद ब्रेझनेव सोवियत संघ के शासक थे। अतत: स्वेतलाना पहले अमेरिका गयीं। बाद में ब्रिटेन की भी नागरिक बनी। पर 2011 में आर्थिक परेशानियों के बीच अमेरिका में स्वेतलाना का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

स्वेतलाना की जीवनी के प्रकाशक ने स्वेतलाना को 25 लाख डॉलर दिया था। उस समय की यह बहुत बड़ी राशि थी। पर इसमें से अधिक पैसे स्वेतलाना ने बांट दिए थे। बाद में वे आर्थिक परेशानियों में रहीं। याद रहे कि ब्रजेश सिंह कम्युनिस्ट थे और मास्को में रहते थे। उत्तर प्रदेश के एक राज घराने से संबंध रखने वाले ब्रजेश सिंह का कम्युनिस्ट होना उतना ही चकित करता था, जितना स्टालिन की बेटी का अपने परिवार और कम्युनिस्ट विचारधारा से विद्रोह करना। स्वेतलाना ने कहा था कि मुझे राजनीति से नफ़रत हैं। मैं खुले वातावरण में रहना चाहती हूं। ख़ैर ब्रजेश सिंह और स्वेतलाना जब अपने-अपने इलाज के सिलसिले में क्रेमलिन के एक अस्पताल में थे तो उन दोनों के बीच प्रेम हो गया। स्वेतलाना ने ब्रजेश से शादी कर ली। पर तकनीकी तौर पर उस शादी की वहां मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन व्यावहारिक रूप से सन 1964 से दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। गंभीर बीमारी के कारण जब सन 1966 में ब्रजेश का निधन हो गया तो स्वेतलाना भारत आईं। पर उन्हें यहां शरण नहीं मिलने पर वह अमेरिका चली गयीं। इस बीच वह कई देशों में घूमती रहीं। स्वेतलाना के गुप्त तरीक़े से अमेरिकी दूतावास की मदद से भारत से चले जाने के बाद लोकसभा में इस पर तीखी चर्चा भी हुई थी।

विदेश मंत्री एम.सी. छागला ने कहा कि 'स्वेतलाना' के प्रति मेरे मन में भी गहरा सम्मान है। क़ानून उसे विवाहिता माने या न माने मैं उसे विवाहिता मानता हूं। उसकी वफादारी और उसका प्रेम किसी भी विवाहिता पत्नी से अधिक है। लेकिन मैं यह पूरी सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि उसने विदेश मंत्रालय के किसी भी मंत्री या अफसर से शरण नहीं मांगी थी न ही वीज़ा बढ़ाने का आग्रह किया था। वह जब भी भारत आना चाहेगी भारत उसका स्वागत करेगा।

लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सांसद डॉ. राम मनोहर लोहिया ने 'स्वेतलाना' के प्रश्न को भारत की विदेश नीति के प्रश्न को उठाया। मंत्री की बात का खंडन करते हुए डॉ. लोहिया ने इलाहाबाद के देवेन्द्र बाहरी को लिखे स्वेतलाना के पत्र को सदन में उधृत किया। उस पत्र के अनुसार जब मैं कालकांकर में न रह सकूंगी क्योंकि राजा साहब यह जानकर खुश हूं कि मैं मास्को जा रही हूं। 'स्वेतलाना' ने इलाहाबाद के जजों तक से अनुरोध किया था कि वे उसे भारत में रहने की इजाज़त दिलाएं। डॉ. लोहिया ने यह भी कहा कि बेहतर होता कि अमेरिका के बजाए स्वेतलाना भारत में ही रहतीं। क्योंकि अमेरिका तो स्वेतलाना को हथियार बना सोवियत संघ को खरोंचेगा। कांग्रेसी सांसद लक्ष्मी कांतम्मा ने कहा कि यदि हमारे आश्रमों और तीर्थों में सैकड़ों विदेशी स्त्रियां रह सकती हैं तो स्वेतलाना भारत में क्यों नहीं रह सकतीं। प्रजा समाजवादी पार्टी के सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी के अनुसार विदेश मंत्री ने राज्यसभा में कहा है कि 'स्वेतलाना'

बाक़ी पेज 11 पर

विराट कोहली बिन शतक सब सून

विराट कोहली के बल्ले से जादुई तीन अंकों का आंकड़ा निकल नहीं रहा है। उनका पिछला शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बना था। उस पारी के बाद से विराट 70 पारियों में कोई शतक नहीं बना पाए हैं। श्रीलंका के ख़िलाफ़ उम्मीद थी कि विराट शतक लगाएंगे लेकिन दो टेस्टों की तीन पारियों में वे 45, 23 और 13 रन ही बना सके। विराट का टैस्ट औसत पांच सालों में पहली बार 50 से नीचे चला गया है। अगस्त 2017 के उनके 60वें टेस्ट में आख़िरी बार उनका औसत 50 से कम होकर 49.55 हुआ था। उसके बाद से उनका कैरियर औसत लगातार 40 टैस्ट से 50 से ऊपर है लेकिन अब उनका औसत 50 से नीचे चला गया है। विराट के अब 101 मैचों में 49.95 के औसत से 8043 रन हैं।

इससे पहले तक उनके बल्ले से टैस्ट में 27 और वनडे में 43 शतक निकल चुके हैं। टी-20 में उन्होंने 97 मैचों में 51.50 के औसत 137.67 के स्ट्राइक रेट से 3296 रन बनाए है लेकिन सवाल यहां टी-30 का नहीं बल्कि टेस्ट और वनडे का है। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि टी-20 प्रारूप के छोटा होने के कारण वे शतक से चूके हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की शुरूआत में उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ अहमदाबाद में तीन टी-20 में नाबाद 73, 77 और 80 रन की पारियां खेली थीं। उनकी वनडे की फार्म भी शानदार रही। उन्होंने पिछली 19 पारियों में 10 अर्धशतक लगाए हैं, जिसमें से चार बार उन्होंने लगातार अर्धशतक लगाए हैं। इस तरह की फार्म से गुज़रने वाले किसी अन्य बल्लेबाज़ पर इतने सवाल नहीं दागे गए होंगे जितने विराट पर दागे गए हैं।

शायद विराट कोहली का वर्तमान शतक का सूखा इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहा है क्योंकि उनके श्रेष्ठ स्तर के किसी खिलाड़ी के लिए यह सामान्य नहीं है। निश्चित रूप से ऊपर जिन 22 खिलाड़ियों के बारे में बताया गया है उनका कुल टेस्ट और वनडे कैरियर में 50 से अधिक का औसत रहा है। कोहली के इन दोनों प्रारूपों में 54.77 के औसत से अब तक 20000 रन बनाए हैं। इन 22 बल्लेबाज़ों में कोहली के करीब अगर कोई है तो वे हैं एंड्रयू स्ट्रॉस, जिन्होंने 38.77 के औसत से टेस्ट और वनडे में 11242 रन बनाए हैं इन बल्लेबाज़ों में शतक के मामले स्ट्रॉस ही हैं जो कोहली के करीब हैं, स्ट्रॉस ने 27 अर्धशतक और कोहली ने 70 अर्ध शतक लगाए हैं। अगर टेस्ट और वनडे में शीर्ष पांच सबसे लंबे शतक के सूखे की बात करें, फिर चाहे बल्लेबाज़ आउट हुए हों या नहीं तो कोहली से ज़्यादा यहां 32 ऐसे मामले हैं। नाट आउट के फायदे को छोड़ भी दें तो कोहली औसत के मामले में पांचवीं रैंक पर आते हैं। डेसमंस हेंस मार्च 1991 से अप्रैल 1993 तक लगातार 70 पारियों में शतक नहीं लगा पाए थे लेकिन उनका इन 32 बल्लेबाज़ों में सबसे ज़्यादा 35.77 का औसत रहा। अगस्त 2017 से जनवरी 2019 तक टैस्ट और वनडे में 49 पारियों के सात अलग-अलग हिस्सों में कोहली 17 शतक बना गए होते, क्योंकि इन 49 पारियों में कोहली ने 26 या 27 बार अर्धशतक लगाया है। कोहली की अब टी-20 अंतर्राष्ट्रीय को शामिल करते हुए 73 पारियां बिना शतक के गुज़र रहे हैं।

विराट कोहली की जगह भारत के कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ एक अच्छी पारी की ज़रूरत है। विराट के कैरियर में 2014 में इंग्लैंड का दौरा एक ऐसा अवसर था जब उनका बल्ला उनसे रुठा रहा था। तब भी कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी लगातार उनका बचाव करते रहे जिसका फायदा आख़िर विराट को मिला। इंग्लैंड दौरे की 10 पारियों में विराट का सर्वाधिक स्कोर 39 रन रहा था। जबकि वनडे सीरीज के चार मैचों में उनका सर्वाधिक 40 रन रहा था। लेकिन धोनी का भरोसा उन पर कायम रहा। इस भरोसे का नतीजा था कि इंग्लेंड से लौटने के बाद वेस्टइंडीज के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज में धर्मशाला में खेले गए तीसने वनडे में उन्होंने 127 रन की शानदार पारी खेली। वनडे में विराट का आख़िरी शतक वेस्टइंडीज के ख़िलाफ 14 अगस्त 2019 को पोर्ट ऑफ स्पेन में बना था तब उन्होंने नाबाद 114 रन बनाए थे लेकिन इस शतक के बाद 21 वनडे में शतक उनके बल्ले से दूर है जबकि इस दौरान उन्होंने दो बार 89 रन की पारियां खेली हैं।❑❑

गर्मियाँ दस्तक दे चुकी हैं रखें अपना ख़ास ख़्याल

गर्मियों ने अपनी दस्तक दे दी है। कहते हैं गर्मी में सूरज अपनी तेज़ किरणों से जगत के स्नेह को पीता रहता है, इसलिए गर्मी में शीतल, मीठा, द्रव खानपान में शामिल करना ज़रूरी है। आयुर्वेद के अनुसार, जब भी घर से बाहर निकलें, कुछ खाकर और पानी पीकर ही निकलें। खाली पेट कभी भी घर से बाहर नहीं निकलें। इन दिनों सलाद खाना विशेष हितकर होता है। मौसमी सब्जियों और फलों का सलाद लें। गाजर, चुकंदर जैसी सब्जियां और सेब, ककड़ी जैसे फल सलाद में शामिल करें। इससे शरीर को न सिर्फ पौष्टिक तत्व मिलेंगे, बल्कि खून की कमी भी दूर होगी और रंगत में निखार आएगा।

गर्मी में तापमान बढ़ने के साथ ही शरीर में पानी की कमी से कई समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में कुछ फल शरीर को हाइड्रेड रखने के साथ पानी का संतुलन भी बनाने में फायदेमंद होत हैं। शरीर में नमी को बरकरार रखने के लिए इस बार सलाद के पत्तों का सेवन करें। इसमें फैट न के बराबर और प्रोटीन प्रचूर मात्रा में होते है और इसमें मौजूद पानी त्वचा में कसावट बनाए रखता है। तेल को अक्सर मोटापा बढ़ाने वाले पदार्थ के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यह अध्ययन में सामने आया कि यह त्वचा की कोशिकाओं को डैमेज होने से रोकने में मददगार होता है। इसलिए दिन में कम से कम एक बार जैतून के तेल का इस्तेमाल त्वचा को नम रखने के लिए ज़रूरी है।

प्यास लगे, तो ही पानी!

अक्सर दिन में कम- से कम 8 गिलास पानी पीने की ताकीद की जाती है, लेकिन किसी भी नियम से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि शरीर में पानी की कमी ही न हो ऐसे उपाए किए जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जब प्यास लगे तब पानी पिया जाए। साथ ही पानी के पूर्ति के लिए कुछ फल भी खाने में शामिल करें। गर्मी की सुस्ती से मुक्ति पाना चाहती है, तो हल्का ठंडा पानी थोड़ी-थोड़ी देर पर पिएं। इससे आपके शरीर में ताज़गी बनी रहेगी, लेकिन खाली पेट हैं, तो ज़्यादा पानी न पिएं। बहुत ज़्यादा पसीना आया हो, तो भी तुरंत पानी नहीं पिएं। सादा पानी धीरे धीरे पिएं। शिकंजी पीना भी आपके लिए सही रहेगी। पानी में नींबू, दही या पुदीना मिलाकर पीना भी सही रहेगा।

लिक्विड डाइट

जूस पानी की पूर्ति का बेहतरीन विकल्प है। ख़ासकर गर्मियों में तो यह बहुत ज़रूरी है। इसे पीने से खून साफ होता है और शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। इसके लिए खीरा, करेला, आंवला, चुकंदर जैसी सब्जियों और तरबूज़ ककड़ी, नींबू आदि फलों का जूस पीकर शरीर और त्वचा को लाभ पहुंचाया जा सकता है। आम पना गर्मी से राहत तो देता ही है, लेकिन मिंट मिस्ट्री (जो पुदीना, खीरा और नींबू के रस को मिलाकर बनाया जाता है) भी गर्मी के लिए फायदेमंद है। यह मिटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत है। इस बार गर्मी में इसे अपनाएं और गर्मी में ठंडक का एहसास पाएं। ग्रीन टी और तरबूज के जूस के साथ शहद मिलाकर पीने से सिर्फ तरावट महसूस होती है बल्कि चेहरा भी खिला खिलाा रहता है। ग्रीन टी बैग को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखें। इस पानी में तरबूज़ का जूस और शहद मिलाएं और ठण्डा करके पिएँ।

जामुन, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट तत्व की मात्रा भरपूर होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत बनाती है। इसका सेवन ज़रूर करें। इसके अलावा सेब को भी डाइट में शामिल करें। इसमें भी एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो आपको गर्मी से भी बचाता है। अगर सेब उपलब्ध नहीं तो संतरा या मौसमी खाएं। इसे खाने से डायटरी फाइबर मिलता है। साथ ही डायजेस्टिव सिस्टम के लिए यह टॉनिक की तरह काम करता है। केला भी गर्मी के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह शरीर में शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है और पाचन प्रक्रिया में भी सुधार लाता है। इसमें मौजूद पोटैशियम और विटामिन-बी पूरे दिन आपको ऊर्जावान रखता हैं यानि जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करें, तो स्नैक्स के तौर पर केले का सेवन सबसे बेहतर उपाय है।

दही में टिव्स्ट

गर्मी के मौसम में दही और बेल का शरबत भी लोग खूब पसंद करते

बाक़ी पेज 11 पर

शेष.... इमरान ख़ान की सरकार....

अनिवार्यत: दिलचस्पी लेती है। मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खुद भी इसी समर्थन का लाभ लेकर सत्तारथ पर सवार हुए थे, लेकिन बीते एक वर्ष से सेना के साथ उनके संबंध लगातार ख़राब हुए हैं। पिछले वर्ष अक्तूबर में नए आईएसआइ प्रमुख के रूप में नदीम अंजुम की नियुक्ति पर इमरान और सेना प्रमुख क़मर जावेद बाजवा के मतभेद सामने आए थे और कुछ समय पहले बाजवा के दूसरे कार्यकाल की संभावना पर इमरान की ठंडी प्रतिक्रिया ने इसे और प्रभावित किया।

पाकिस्तान में राजनीतिक दल फैसला लेने से पहले पिंडी (रावलपिंडी- जहां सेना मुख्यालय है) के सिग्नल को देखने के अभ्यासी रहे हैं, जो अब तक खामोश हैं। इससे बेचैनी इमरान को भी है, जो 'सरकार को सेना के समर्थन' की बात लगातार दोहराते रहे हैं, लेकिन अब वह भी धैर्य खो रहे हैं।

शुरू में सरकार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर टालमटोल भरा रवैया अपनाया गया था और उसके लिए संसद के कमरों की मरम्मत जारी होने 23 मार्च को प्रस्तावित इस्लामिक देशों के सम्मेलन के चलते सत्र न बुला पाने की बात कही गई थी। पर अब सरकार को भी लग रहा हे कि इसे टोलना कठिन है। विपक्ष तय वक्त पर होने वाले चुनाव का इंतज़ार करने से पहले सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है इसलिए अब इमरान भी आर-पार की जंग के लिए बाध्य हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, अमेरिकी बेरुखी तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की सिकुड़ती मदद के चलते अलोकप्रियता के बोझ से टूटने की कगार पर खड़ी अपनी सरकार के गिर जाने से पहले वे तीखे हमले करेंगे और अपने वही पुराने आरोप दोहराएंगे कि भ्रष्टाचार के आरोपी विपक्षी नेताओं ने अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई रोकने के लिए उनकी सरकार गिरा दी। ऐसा करके शायद वह अगले चुनाव में अपने एक भावनात्मक समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे, जिसकी उपयोगिता इस उपमहाद्वीप की राजनीति में हमेशा से अहम रही है।❑❑

शेष.... जब देश की बहू....

और दिनेश सिंह के बीच व्यक्तिगत मामला है और सरकार उसमें नहीं पड़ना चाहती। सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने यहां तक कहा कि यह चाची और भतीजे का झगड़ा नहीं है बल्कि एक राजनीतिक मामला है।

वह सब कुछ छोड़कर भारत में रहने आई और भारत सरकार ने उसे रहने की इजाज़त नहीं दी। मधु लिमये ने सदन को बताया था कि न्यूयार्क टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार 'स्वेतलाना' ने कहा था कि अगर मुझे भारत छोड़ने के लिए कहा गया तो मैं यमुना में कूद जाऊंगी या कुतुब मीनार से छलांग लगा लूंगी। सी.पी. एम. के उमानाथ ने यह कह कर सदन में सनसनी फैला दी कि 'स्वेतलाना' लखनऊ में एक सी0आई0ए0 एजेंट के साथ सिनेमा देखने गयीं थीं। उसे एक अमेरिकी एजेंट ने रातोंरात भारत से बाहर जाने दिया। भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत ने बाद में यह लिखा था कि उन्होंने 'स्वेतलाना' को भारत से सुरक्षित बाहर भेजने का प्रबंध कर दिया था। 'स्वेतलाना' को सन 1978 में अमेरिकी नागरिकता मिल गयी थी। कुछ समय के लिए वह ब्रिटिश नागरिक भी रहीं। 1984 में वह सोवियत संघ वापस लौटीं थीं। पर फिर वह अमेरिका गयीं। वहीं 2011 में 'स्वेतलाना' का निधन हो गया। कुल मिलाकर 'स्वेतलाना' का जीवन हलचलपूर्ण और उदास ही रहा।❑❑

शेष....गर्मियाँ दस्तक दे चुकी हैं...

हैं। गांवों में छाछ और दही के शर्बत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यही नहीं लोग वहां दूध में गुलाबजल मिक्स करके भी शरबत बनाते हैं, ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिले। यही देसी उपाय बाजार में भी उपलब्ध होने लगा है फ्लेवर्ड दही के रूप में। अगर आप बाजार में इसे नहीं लेना चाहतीं, तो रसभरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबरी...किसी भी बेरी के साथ दही को मिक्स करके गर्मियों का एक स्पेशल पेय बना सकती है। यह आइसक्रीम से कहीं ज़्यादा बेहतर और गर्मी के मौसम के मुताबिक फायदा पहुंचाने वाला होता है। दही में भुना जीरा पाउडर और काला नमक मिलाकर भी खा सकती है। दही त्वचा संबंधी परेशानियों में लाभदायक तो होती ही है, साथ ही यह आपके हाज़मे के लिए भी ज़रूरी है।❑❑

शेष....द्रविड़ राजनीति के लिए नए सबक़

तवज्जोह देकर भाजपा उत्तर भारतीय जनता पार्टी होने की अपनी छवि को भी तोड़ने का प्रयास कर रही है। एक कोशिश द्रमुक को अपनी ओर लुभाने की हो रही है।

बहरहाल, स्टालिन की छवि को अब कहीं ज़्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को आगे करके हमला बोलती है, विशेषकर जब चुनाव लोकसभा के हों। द्रमुक निश्चित तौर पर भाषा और स्थानीय पहचान की अपनी ताक़त के बूते चुनाव में उतरेगा, लेकिन संसद में पर्याप्त सदस्यों को भेजने के लिए उसे अपनी रक्षा पंक्ति को मज़बूत करना होगा। संभवत: इसीलिए, द्रमुक खुद को एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में भी पेश करने लगा है, जो धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है। उसके नेता अब नास्तिक होने की अपनी पुरानी पहचान से भरसक बचने की कोशिश करने लगे हैं।❑❑

कृषि कानूनों पर घनावत के दावों को किसान नेताओं ने बताया झूठ का पुलिंदा, कहा- यह सिर्फ कार्पोरेट के पक्ष में प्रचार

कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के एक सदस्य अनिल घनावत द्वारा यह दावा करने पर कि देश के 85 फीसदी किसान उन कृषि कानूनों के पक्ष में हैं जिन्हें किसान आंदोलन के दबाव में मोदी सरकार ने वापस ले लिया था, किसान नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। इन किसान नेताओं ने घनावत के दावे को झूठा करार दिया है। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने घनावत के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा प्रचार है, वहीं स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने इसे बकवास बताया है। नेशनल हेरल्ड से बातचीत में हन्नान मोल्लाह ने कहा कि, घनावत के दावे झूठे डाटा पर आधारित हैं जिन्हें सिर्फ ऑनलाइन फीडबैक के आधार पर बनाया गया है, क्योंकि घनावत लंबे समय से कृषि क्षेत्र को कार्पोरेट के हाथों में देने की वकालत करते रहे हैं। मोल्लाह ने कहा कि जाहिर है कि वे कृषि कानूनों के पक्ष में ही बोलेंगे। अनिल घनावत किसानों के एक संगठन शेतकारी संगठना के सदस्य हैं, जिसे शरद जोशी ने 70 के दशक में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया था। घनावत ने सोमवार को कृषि कानूनों पर कोर्ट की समिति के कुछ हिस्से जारी करते हुए इन कानूनों को लागू करने की बात कही थी। घनावत पूर्व में सुधारों के पक्ष में आंदोलन भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 19 मार्च 2021 को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिर कर दी थी। हमने इसके बाद तीन बार कोर्ट को पत्र भी लिखा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लेकिन चूंकि कानून वापस लिए जा चुके हैं, इसलिए अब इस रिपोर्ट का कोई अर्थ नहीं रह गया है। घनावत के दावों को झूठ का पुललदा बताते हुए मोल्लाह ने कहा कि घनावत कार्पोरेट एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट और एक किसान नेता के रूप में घनावत की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग शेतकारी संगठन को किसानों का संगठन नहीं मानते हैं, क्योंकि यह संगठन किसानों के बजाए हमेशा कार्पोरेट के पक्ष में ही बोलता रहा है। मोल्लाह ने नेशनल हेरल्ड में प्रकाशित उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कानूनों की वापसी के बावजूद हरियाणा की बीजेपी सरकार ने खाद्य निगम को गेहूं का भंडारण अडानी के गोदामों में करने का निर्देश दिया है। मोल्लाह ने कहा कि कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी में सिवाए भारतीय किसान यूनियन नेता भूपिंदर सिंह मान के अलावा सभी सदस्य शुरु से ही कृषि कानूनों के पक्षधर रहे हैं। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में एक कमेटी बनाई थी जिसमें अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल घनावत के साथ ही भूपिंदर सिंह मान को भी शामिल किया था। कमेटी ने पिछले साल 19 मार्च को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी। लेकिन मोदी सरकार ने पिछले साल नवंबर में ऐन विधानसभा चुनावों से पहले तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था।

स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने भी घनावत के दावों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे योजित बकवास करार दिया है। योगेंद्र यादव ने सवाल पूछा कि क्या घनावत किसी ऐसे किसान से मिले हैं जो इन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था? याद दिलादें कि 40 किसान यूनियनों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी का बहिष्कार किया था।❑❑

शेष.... प्रथम पृष्ठ

ानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जिन पर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में सफल होकर आए 402 सदस्यों में से 143 (36 प्रतिशत) अपने चुनावी शपथ पत्र में अपने ऊपर आपराधिक मुकदमें की बात कही थी। जबकि मुख्य आपराधिक मामलों का सामना करने वाले विधान सभा सदस्यों की संख्या 107 थी जो विधानसभा के सदस्यों का 26 प्रतिशत बनता है। इस तरह 2012 की सूबाई असेम्बली में आंकड़े क्रमश: 47 प्रतिशत (189 विधान सभा सदस्य दाग़दार छवि वाले) और 24 प्रतिशत (98 सदस्य अहम मामलों में अपराधी) थे।

इसलिए हर चुनाव के बाद आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की सफलता का ग्राफ बढ़ रहा है जिस से मालूम होता है कि राजनीतिक दल भी यह मानते हैं कि आपराधिक तत्व ही जीत की गारंटी हैं और चूंकि चुनाव में हर हाल में जीत प्राप्त करना ही तमाम राजनैतिक दलों का उद्देश्य होता है इसलिए वह इसके लिए हर तरीक़ा अपनाने को तैयार रहते हैं। जिन से उनकी मौजूदगी सदन में अधिक से अधिक हो सके।

कुछ जनप्रतिनिधि यह दलील देते हैं कि राजनीति से प्रभावित होकर मुकदमात उन पर लादे गए हैं यह कुछ हद तक सही भी है, मगर चुनाव आयोग ने तो इसके लिए मापदंड निर्धारित किए हैं, मुकदमा अगर सालभर से अधिक है, प्रत्याशी पर पांच साल या उस से अधिक की सज़ा वाले जुर्म का इल्ज़ाम हो, निचली अदालत में चार्जशीट पेश कर दी गयी हो और कोर्ट ने उन्हें मंज़ूर कर लिया हो। आयोग का मानना है कि इस तरह प्रत्याशियों को चुनाव में टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। मगर मुश्किल यह है कि राजनैतिक दल अभी तक इन सिफारिशों को अमल में लाने की इच्छाशक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं।

दाग़दार छवि वाले लोग एक ओर तर्क भी देते हैं कि न्यायालय से जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए वह बेगुनाह हैं, मगर यहां प्रश्न यह है कि भारत की जेलों मे चार से सवा चार लाख क़ैदी हैं जिनमें से 2 लाख 71 हजार के लगभग विचाराधीन हैं। न्यायालय में उन पर मामले चल रहे हैं और वह अभी तक अपराधी साबित नहीं हुए हैं, यानि कि बेगुनाह हैं, इस तरह से वह बेगुनाह लोगों को हमने जीवन बिताने, कारोबार की आज़ादी, आज़ादी से घूमने फिरने का अधिकार, बा-इज्ज़त ज़िन्दगी गुज़ारने जैसे अधिकार वंचित कर रखा है, उनका क्या होगा जब कानूनी दायरे में उन 2071 लाख विचाराधीन क़ैदियों के कई अधिकार छीन लिए गये हैं तो दाग़दार प्रत्याशियों को कुछ दिनों तक चुनाव लड़ने से रोक देने में आख़िर कौन सी रुकावट है। वैसे भी चुनाव लड़ना कोई बुनियादी अधिकारी तो है नहीं, अगर हम उनको उनके कहने के अनुसार निर्दोष होने के आधार पर चुनाव लड़ने की छूट दे सकते हैं, तो उसी तर्क पर विचाराधीन क़ैदियों को रिहा क्यों नहीं कर सकते, उनसे उनके बुनियादी अधिकार हम क्यों छीन रहे हैं।

राजनीति में अपराध के प्रवेश को रोकने का एक तरीक़ा नोटा (मौजूदा में से कोई नहीं) भी है, यह भारतीय वोटरों को मिला ऐसा अधिकार है, जिसके द्वारा वह दाग़दार छवि वाले प्रत्याशियों को आईना दिखा सकते हैं, और जहां चुनाव में नोटा के लिए अधिक वोट आएं तो वहां चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव कराए जाएं। इस से राजनीतिक दलों को भी यह एहसास होगा कि वह चुनावी जंग में जिन प्रत्याशियों पर दांव लगा रहे हैं, वोटर उनको पसंद नहीं करते। इससे वह दाग़दार प्रत्याशियों से दूरी बना सकते हैं। नोटा के दायरे में ही 'मना करने का अधिकार' लाया जाना ज़ाहिर है उसके लिए जनता को जागरुक होने की सख़्त आवश्यकता है।

बहरहाल यह एक कड़ी सच्चाई है कि विधायी संस्थाओं में दाग़दार और अपराधी प्रवृत्ति के सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो हमारी आज़ादी और लोकतंत्र के लिए भारी ख़तरा है जिस पर तमाम राजनैतिक दलों को विचार करना चाहिए और कानूनी विशेषज्ञों और चुनाव आयोग को साथ लेकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो राजनीति को अपराधीकरण से स्वच्छ करने का कोई रास्ता निकाला जा सके।❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **20March2022** Posting Days : **MON-TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र **मीम.सीन.जीम**

•आप की नई चुनौती •ज़रूरी है सुरक्षा कवच •दाग़ी प्रतिनिधि

आप की नई चुनौती

आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। यह शपथ शहीदे आज़म भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कलां में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौजूदगी के बीच ली गई। शपथ ग्रहण समारोह की यह सांकेतिकता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम वह विश्वास जो पंजाब के लोगों ने इस अपेक्षाकृत नई पार्टी को 117 में से 92 सीटों का विशाल बहुमत सौंपकर जताया है। जिस तरह से कांग्रेस और अकाली दल और भाजपा जैसी पारंपरिक पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया, वह बताता है

> **किसान आंदोलन में पंजाब ही सबसे आगे रहा। वहां किसानों की बदहाली बढ़ी है। उनकी स्थिति में सरकार कैसे बेहतरी लाती है, यह भी देखने की बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की यह नई पारी पूरे देश की राजनीति में एक नए प्रयोग के रूप में देखी जा रही है। भविष्य में इसकी सफलता या नाकामी के गहरे निहितार्थ होंगे।**

कि पंजाब के लोगों ने इस बार वोट देते हुए नई पार्टी से उम्मीदों के साथ ही अपनी पुरानी पार्टियों के प्रति निराशा और रोष भी प्रकट कर दिया। ज़ाहिर है, यह स्थिति भगवंत मान की अगुआई में बनी इस नई सरकार पर ज़िम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ डालती है। निश्चित रूप से पंजाब के लोगों में जगी इन उम्मीदों के पीछे पार्टी के बहुप्रचारित दिल्ली मॉडल की भी अहम भूमिका रही है जिसे सस्ती बिजली, पानी और अच्छी शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं की गारंटी के रूप में पेश किया जाता रहा है। पार्टी ने पंजाब में खासतौर पर 18 वर्ष से ऊपर की आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपये मासिक देने, हर घर को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने, हर गांव और कस्बे के वार्डों में मोहल्ला क्लीनिक बनाने जैसे वादे किए हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यह कर्ज़े के बोझ से लदा है। इस पर 02 लाख 82 हज़ार करोड़ का कर्ज़ हैं ऐसे में देखना होगा कि नई सरकार अपने वादे पूरे करने की मौन सी राह निकालती है। इसके साथ ही बार्डर स्टेट होने के नाते पंजाब काफी संवेदनशील माना जाता है। आतंक के दौर को यह राज्य पीछे ज़रूर छोड़ चुका है, लेकिन ख़ालिस्तान समर्थक तत्वों की साज़िशों की बातें जब तब उठती रहती हैं। ड्रग्स यहां एक बड़े मुद्दे के रूप में रेखांकित होता रहा है। चूंकि दिल्ली में पुलिस व्यवस्था का ज़िम्मा राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता और वहां आम आदमी की सरकार इसे मुद्दा बनाती रही है, इसलिए इस पर पूरे देश की नज़रें टिकी रहेंगी कि पंजाब में क़ानून व्यवस्था के मसले को नई सरकार कैसे संभालती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि किसान आंदोलन में पंजाब ही सबसे आगे रहा। वहां किसानों की बदहाली बढ़ी है। उनकी स्थिति में सरकार कैसे बेहतरी लाती है, यह भी देखने की बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की यह नई पारी पूरे देश की राजनीति में एक नए प्रयोग के रूप में देखी जा रही है। भविष्य में इसकी सफलता या नाकामी के गहरे निहितार्थ होंगे।

ज़रूरी है सुरक्षा कवच

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 12 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का टीकाकरण अभियान चल रहा है। दिल्ली में इस आयु के लगभग 10 लाख बच्चे हैं। इन्हें टीका लगाने के लिए 12 अस्पतालों सहित 140 केन्द्र बनाए गए हैं। मार्च माह के मध्य में शुरू हो चुके इस टीकाकरण में शुरूआती सप्ताह में 6 लाख से अधिक टीके की खुराकें यहां पहुंच गई हैं। इससे स्पष्ट है कि इन बच्चों के टीकाकरण को लेकर सरकार गंभीर है। कोरोना से बचाव के लिए यह ज़रूरी भी है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नियमित रूप से चल सके, इसके लिए यह ज़रूर है कि सभी बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। इसे ध्यान में रखकर तीन जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। हालांकि शुरूआत में टीकाकरण केन्द्रों पर बच्चों की संख्या कम दिखी पर अब इस टीकाकरण ने ज़ोर पकड़ लिया है और अत्याधिक संख्या में इस आयु वर्ग के बच्चे टीका लगवा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों का टीकाकरण संभव हो सकेगा। कोरोन संकट की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। लगभग दो सालों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। स्कूल कॉलेज नहीं जाने से छात्रों में कई तरह की परेशानियां भी देखी जा रही हैं। कोरोना काल से पहले की तरह स्कूलों में पढ़ाई हो सके, इसके लिए टीकाकरण अभियान को सफल बनाना दिल्ली सरकार का प्रथम उद्देश्य है। साथ ही पूरी सावधानी रखनी होगी। कोरोना से बचाव के लिए जारी आवश्यक दिशा निर्देशों का सख़्ती से पालन होना चाहिए। यह ध्यान रखना होगा कि कोरोना संक्रमण का ख़तरा कम हुआ है, पर अभी ख़तरा पूरी तरह से टला नहीं है, प्रत्येक बच्चे और स्कूल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को सतर्कता के साथ इस टीकाकरण को सफल बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

दाग़ी प्रतिनिधि

हम अपने अनेक कॉलमों में इस सामाजिक बुराई का वर्णन कर चुके हैं। आजकल जो एक बात हर ओर चर्चा का विषय बनती जा रही है वह है राजनीति अपराध जगत का बढ़ता प्रवेश। राजनीति के अपराधीकरण को लेकर देश में सभी पार्टियां चिन्ता ज़ाहिर ने करने में एक दूसरे आगे दिखती हैं, पर असल में सभी पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है कि चुनाव में बस जितना है प्रत्याशी का बैकग्राउंड रिकॉर्ड कैसा भी हो बस प्रत्याशी जिताऊ हो। जब कानून बनाने की बात आती है तो अमूमन सभी दल इस ज़िम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वह बेवजह नहीं है कि इस समस्या को लेकर चिंता लंबे समय से जताई जाती रही है, मगर कोई सुधार होने के बजाय इसमें बढ़ोत्तरी ही होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या इससे पहले के चुनाव तकरीबन चुनाव-चुनाव अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीतिक दलों की पसंद और मजबूरी बनते जा रहे हैं। ज़्यादातर मुख्य पार्टियों ने अपराधिक छवि या पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दिया और उनके जीत कर विधान सभा में पहुंचने के रास्ते तैयार किए। इसमें हाल के चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी से लेकर नतीजों में दूसरे स्थान पर रहने वाली समाजवादी पार्टी तक शामिल हैं। प्रश्न है कि चुनाव प्रचार में जनता के सामने राजनीति में अपराधियों को ठिकाने लगाने के वायदे करते हुए क्या पार्टियां महज़ ऐसा बोलने का बस दिखावा मात्र करती हैं?

दाग़ी जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव प्रचार करना भी राजनीतिक दलों के लिए समय की मांग जैसा हो गया है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों के जनता के प्रति जवाबदेह होने के दावे और सरोकार की असलियत का अंदाज़ा इससे भी लगता है कि चुने गए 91 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। पिछली बार 80 प्रतिशत विधायक इस वर्ग के थे। ज़ाहिर है, आम और वंचित तबक़ों की जनता की जगह राजनीति की मुख्यधारा में लगातार कम होती जा रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि समूचे देश की राजनीति में जिस समस्या को बेहद गंभीर मानकर सभी दल इसके हल की बातें करते रहते हैं, वह हर अगले चुनाव के दौरान और बाद में और ज़्यादा जटिल बनकर उभर जाती है। विचित्र यह है कि सत्ताधारी से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियों एक दूसरे पर ऐसे आरोप लगाते नहीं थकतीं कि वे राजनीति में अपराधियों को बढ़ावा या संरक्षण दे रही हैं, और इन आपराधी प्रवृत्ति के लोगों से अपने दूसरे स्वार्थ सिद्ध कराने से भी गुरेज़ नहीं करती। इस बार के चुनावों के पहले राजनीति के अपराधीकरण पर क़ाबू पाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट देने की वजह बताने को कहा था। इसके अलावा, प्रत्याशियों को इसे सार्वजनिक करना था। मगर ऐसा लगता है कि न तो राजनीतिक दलों पर इसका असर पड़ा, न अपने अपराधों के रिकॉर्ड के साथ राजनीति में अपने जगह बनाने वाले लोगों पर।

इस क्रम में अगर गहराई से देखा जाए तो चुनाव आयोग की भूमिका भी सीमित सी होती जा रही लगती है।

> **हाल के चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी से लेकर नतीजों में दूसरे स्थान पर रहने वाली समाजवादी पार्टी तक शामिल हैं। प्रश्न है कि चुनाव प्रचार में जनता के सामने राजनीति में अपराधियों को ठिकाने लगाने के वायदे करते हुए क्या पार्टियां महज़ ऐसा बोलने का बस दिखावा मात्र करती हैं?**

चुनाव आयोग चुनाव के समय पर बड़े-बड़े होर्डिंग और विज्ञापन में यह बात कहती नज़र आती है कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रत्याशी न बनाया जाए, पर इन बातों पर न तो कोई दल और न ही कोई पार्टी कोई ध्यान देती। इसका एक पहलू यह भी है कि चुनाव आयोग ने आज तक कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की या करना नहीं चाहती जिससे राजनीतिक दल इन अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएं।□□

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ **Paytm** या **PhonePe** द्वारा **9811198820** पर **SHANTI MISSION**
❸ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: **Indraprastha Estate**
IFS Code: **SBIN0001187**

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक मोहम्मद तैयब ख़ान ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173